

Supplementary Demands for Grants and Demands for Excess Grants

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 17 और 18 एक साथ लिए जाएंगे।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों और अतिरिक्त अनुदानों की पूरक मांगों।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

?कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10, 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 33, 35 से 38, 43 से 56, 58 से 66, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 85 से 98 और 100 से 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।?

<image: image007.gif>

<image: image008.gif>

और

?कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 15 और 18 के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।?

<image: image009.gif>

श्री गौरव गौरव गोगोई।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने वाले हैं, तो आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी उचित समझेंगी कि वे स्वयं यहां आकर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों की बातें और जनता की बातें सुनने का प्रयत्न करें। सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में लगभग 80 ग्रांट्स हैं, चार एप्रोप्रिएशन हैं और लगभग 1,19,000 हजार करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी ग्रांट्स हैं। मैं सबसे पहले सप्लीमेंटरी ग्रांट के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले क्वार्टर टू जीडीपी का डेटा जनता के सामने प्रकाशित हुआ। यदि आप उसकी गहराई में जाएंगे तो कुछ चिंताजनक विषय आपको मिलेंगे। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में हमारा क्वार्टर टू जीडीपी इतना अच्छा नहीं हुआ है। यदि एग्रीकल्चर के सब्सिडेशन में जाएंगे तो उसमें कटौती हुई है, ग्रोथ की बजाए उसमें रिग्रेशन हुआ है और इसका कारण वर्तमान की बारिश, मानसून, एलनिनो इफेक्ट का प्रभाव हमें दिख रहा है।

ऐसे संदर्भ में, मैं आशा कर रहा था कि इस सत्र के पूर्व शायद सरकार ने मनरेगा के लिए अतिरिक्त वित्तीय राशि मांगी होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक जितनी राशि मनरेगा के लिए रखी है, वह संतोषजनक नहीं है और मैं अपेक्षा करूंगा कि इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में वे मनरेगा के लिए अतिरिक्त रकम लाएंगे क्योंकि आज भी मनरेगा की बहुत डिमांड हमारे देश में दिख रही है और यह आपके डेटा में भी है कि मनरेगा की डिमांड पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, घटी नहीं है।

आदरणीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस सरकार से सेन्सस-2021 का भी विवरण चाहते हैं। मुझे याद है, आज से लगभग एक-डेढ़ वर्ष पहले आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में सेन्सस के लिए कुछ राशि एलोकेट की थी, लेकिन उसके पश्चात्, अब तो कोविड भी खत्म हो गया है, इसे खत्म हुए लगभग दो साल हो गए, लेकिन सेन्सस-2021, जो होना है, उस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस कदम हम नहीं देख पा रहे हैं। इस साल के बजट में भी इसका कोई विवरण नहीं दिखा और न ही सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में भी इसके लिए कुछ दिख रहा है। हम बार-बार सेन्सस की मांग कर रहे हैं, देश की जनता यह मांग कर रही है कि एक कास्ट सेन्सस होना चाहिए। इसमें पूरा कास्ट डेटा आना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि यह सरकार वर्ष 2021 के सेन्सस को कब प्रकाशित करेगी, हमारी वित्त मंत्री जी इसके बारे में आज स्पष्टीकरण दें।

महोदय, तीसरी बात यह है कि बहुत दुःख की बात है कि यही वह देश है, जिसमें हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान?' का नारा दिया था। मैंने किसान की बात तो कह दी है कि आज किसान जलवायु परिवर्तन और विभिन्न परिस्थितियों से लड़ रहा है और उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन जवानों के साथ भी आज यह सरकार अन्याय कर रही है। आज यह सरकार डिसैब्लिटी पेन्शन को लेकर भी बार-बार प्रश्न उठा रही है और यह कितने अफसोस की बात है कि हमारे जवान, जो अपने गांव, अपने घरों से दूर रहकर सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं, आज उनकी डिसैब्लिटी पेन्शन पर भी इस सरकार की आँख है और इन्होंने डिसैब्लिटी बेनिफिट्स को कम कर दिया है। ऐसे जवानों को, जिन्हें एक वर्ग के तहत डिसैब्लिटी पेन्शन मिल रहा था, उसको भी यह सरकार और रक्षा मंत्रालय कोर्ट में जाकर

चैलेंज कर रहा है। यह कितने अफसोस की बात है कि न तो किसानों को सम्मान मिल रहा है, न जवानों को सम्मान मिल रहा है।

इसी संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज आप अग्निवीर स्कीम लाए हैं, लेकिन हमारे अलग-अलग प्रदेशों में सैनिक स्कूल की मांग हो रही है। मेरे ही प्रदेश असम में हम बार-बार इसकी मांग कर रहे हैं। हमने इसके लिए भूमि भी ठीक कर दी है। हम यह मांग कर रहे हैं कि गोलाघाट जिले में एक दूसरा सैनिक स्कूल होना चाहिए, जिसका विवरण इससे पहले मनोहर पर्रिकर जी, जो इससे पहले देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने किया है। असम की राज्य सरकार के बजट में भी यह उल्लिखित है कि गोलाघाट जिले में दूसरा सैनिक स्कूल होना है, लेकिन आज तक हमने जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं देखा, कोई काम नहीं देखा।

सर, इसके साथ-साथ मैं डिजास्टर रिलीफ की भी मांग करता हूं। कुछ ही दिन पहले केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए कुछ बजट रिलीज किया, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, तमिलनाडु का जो ड्यू है, under the State Disaster Response Fund, only their due has been released. But the additional damage caused by floods in Chennai, the burden of that now falls on the State Government and the Centre is not doing enough.

They talk about Cooperative Federalism, but there is no additional aid that is offered to States at the time of natural disasters whether it is floods in Chennai, whether it is cyclone in Andhra, whether it is landslide that we saw in Himachal Pradesh or whether it is landslide that we saw in Sikkim. In Sikkim, the amount of fund that was released was miniscule. It was pitiable.

आप ?लुक ईस्ट?, ?एक्ट ईस्ट?, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन सिक्किम में जब एक डिवाइसेशन हुआ, जिसमें लोगों की जानें चली गयीं, the amount of fund that was released was miniscule. I urge this Central Government, in the spirit of cooperative federalism कि जब किसी राज्य में आपदा आती है तो उनका जो ड्यू है, उसे तुरन्त रिलीज करें, लेकिन उस राज्य को जो अतिरिक्त री-इम्बर्स करना चाहिए, वह भी ये करें, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस सप्लिमेंट्री ग्रांट्स में, मैं नेशनल हाइवे का भी उल्लेख करना चाहूंगा। असम में नेशनल हाइवे आईडीसीएल का एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है। लेकिन किसी भी प्रकार से उनका काम ज़मीन पर अच्छा नहीं है, असंतोषजनक है औ। उसमें प्रश्न उठ रहे हैं। आज नोमालीगढ़ से डिब्रुगढ़, जो फोर लेन हाइवे है, टिओक-शिवसागर पार्ट पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। वहां पर आज फेज़ 1 के एक्सपेंशन का काम हो गया है। लेकिन वह काम वहीं पर रह गया है और फेज़ 2 और फेज़ 3 अभी तक हुआ नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि जो अपर असम है, जहां पर पर्यटक आते हैं, आज वहां पर किसी प्रकार का काम हुआ नहीं है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी यह करती है कि जब लोगों की भूमि लेती है तब उनको कम्पनसेशन देती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को काम्पनसेशन देना एक स्कैम बन गया है, क्योंकि कुछ लोग आज लैण्ड के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखा कर एनएचआईडीसीएल के कुछ अधिकारियों के साथ बात कर के स्कैम के द्वारा लाखों रुपये का कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। विशेष रूप से ऐसा हम कार्बी एंगलॉन्ग में देख रहे हैं, एनएच 29 में, पारोख्वा, लाहौरिजन के एरिया में बहुत से फर्जी लोगों को वहां पर फर्जी लैण्ड दिखा कर

एनएचआई से बहुत सी रकम ले ली है। मैं चाहता हूँ कि आज यह रिकॉर्ड पर जाए और एनएचआईडीसीएल पर एक जाँच बैठे कि कहाँ-कहाँ उन्होंने इस प्रकार के फर्जी काम किए हैं।

सर, मैं ब्रॉडली अब इस सप्लिमेंट्री ग्रांट्स से बाहर आना चाहता हूँ कि सप्लिमेंट्री ग्रांट्स पर हम यह देख रहे हैं कि बार-बार सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी जीडीपी बहुत आगे बढ़ रही है, आज बहुत सी प्राइवेट इनवेस्टमेंट, एफडीआई हो रही है। सर, लेकिन देश की जो असली अवस्था है, देश की जो वास्तविकता है, वह हमने कुछ दिनों पहले उत्तराखण्ड में देख ली है। उत्तराखण्ड में केंद्र सरकार का 12,000 करोड़ रुपये का एक सुरंग बनाने का प्रोजेक्ट था, उस सुरंग में हमारे लगभग 41 मज़दूर लगभग 2 हफ्ते फंस गए थे। उनके फंसने का कारण था कि टनल निर्माण करते हुए जो एक एस्केप पैसेज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए होना चाहिए था, वह एस्केप पैसेज उनके लिए नहीं था। यह तो मैं आभार प्रकट करता हूँ, विभिन्न एजेंसियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा लोगों का जिन्होंने उन 41 वर्कर्स को बाहर निकाला। लेकिन क्या इंकवायरी होगी कि उत्तराखण्ड के सिल्वियारा टनल में ऐसा क्यों हुआ कि टनल को कोलैप्स होना पड़ा? एस्केप पैसेज क्यों नहीं था? क्या इसकी इंकवायरी होगी? क्या हम दोबारा उन मज़दूरों को भूल गए हैं? यही आज सच्चाई है। करोड़ों का प्रोजेक्ट बना कर सरकार हाईवे तो बनाती है, लेकिन जो इंकवायरी होनी चाहिए, जो सुरक्षा हमारे मज़दूरों को देनी चाहिए, वह सुरक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। जब रैट होल माइनर्स ने लोगों को निकाला तो उन्होंने अंत में क्या बोला? उन्होंने अंत में यह बोला कि हमने इन सभी लोगों को बचाया, हम सरकार से बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। यही देश की आज वास्तविकता है कि हर वह मज़दूर, हर वह श्रमिक, हर वह किसान, चाहे शहरी इलाके में हो या चाहे गांवों में हो, आज बढ़ती हुई मंहगाई में वह चाहता है कि सरकार मेरा वेतन बढ़ाए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि विशेष रूप से महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज लेबर फोर्स में घट रहा है। आज असमानता बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार यह बताए, आज कोविड के पश्चात दो साल गए हैं, लेकिन महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज लेबर फोर्स में घट क्यों रहा है? आप आज का इकोनॉमिक्स टाइम्स या बिज़नेस स्टैंडर्ड देख लीजिए, अज सैलरीड सैक्टर में भी महिलाओं की जो सैलरी है, compared to men is far less. There is a huge gender gap that is happening and that should worry us because we want our Indian women to be empowered financially, socially, and politically. It pains and disturbs us that irrespective of a woman working on a field, in a mine or in a company, she is discriminated against and she is not getting fair wages and equal wages. Therefore, we see a greater income inequality that is taking place. Women are facing the greatest brunt of income inequality. This is a very disturbing fact for India. Even the United Nations Development Programme has said that in India, top 10 per cent hold 15 per cent of the national income. The top 10 per cent hold 15 per cent of the national wealth.

जबकि 10 प्रतिशत आबादी के पास ही 50 प्रतिशत नेशनल इनकम है, लगभग 15 परसेंट नेशनल वेल्थ है। हम यही देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन जो फल है, वास्तव में जो अच्छे दिन आ रहे हैं, वह अच्छे दिन देश के सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर लोग आज भी सरकार द्वारा दिए जाने वाली फ्री अनाज पर निर्भर हैं। हम बात करते हैं कि हम फिफथ लार्जस्ट इकोनॉमी हैं, थर्ड लार्जस्ट इकोनॉमी हैं, लेकिन आज भी हमें अपनी 80 करोड़ आबादी को फ्री में राशन देना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे लोग भुखमरी की समस्या झेलेंगे। यह हमारे देश की सच्चाई है। इससे हमें भागना नहीं चाहिए। देश की इस सच्चाई को हमें कबूल करना चाहिए, न कि बार-बार राजनीति करनी चाहिए। यह सरकार बार-बार अपना सीना

ठोकती है और कहती है कि हमने फ्री में अनाज दिया, लेकिन वह फ्री अनाज किस एक्ट के जरिए दे रही है? वह जो फ्री अनाज दे रही है, वह नेशनल फूड सिक्वोरिटी एक्ट के जरिए दे रही है। यह एक्ट यूपीए सरकार के दौरान पारित हुआ था। आज उसी एक्ट के द्वारा यह फ्री राशन दिया जा रहा है।

महोदय, यह सरकार बार-बार जैम ट्रिनिटी की बात करती है, यह सरकार बार-बार यूपीआई की बात करती है, लेकिन यूपीआई और जैम ट्रिनिटी के जो दो मूल पहलू हैं, वह आधार है। इसका ढांचा भी यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया था। यूपीए के समय ही लोगों के हाथों में मोबाइल, स्मार्ट फोन और चीप डेटा हो गया था। इसीलिए, मैं चाहता हूँ कि यह सरकार कबूल करे कि यह जो प्रगति है, उसमें सारी सरकारों की भूमिका है। इस देश का जो इतिहास है, उसे दोबारा लिखने की कोशिश यह सरकार न करे। देश के इतिहास को सिर्फ अपने राजनीतिक ढंग से सोचने की कोशिश न करें।

सर, हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जीडीपी के बारे में बोले। आज भी हमारे जो लेबर इंटेन्सिव सेक्टर हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, होटल एंड कम्युनिकेशन हो, वहां इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुए हैं। यहां पर लेबर इंटेन्सिव इंडस्ट्रीज हैं। आज जो लेबर इंटेन्सिव इंडस्ट्रीज हैं, उनकी वास्तविक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार बताए कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, होटल, कम्युनिकेशन, अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल क्षेत्रों में, जहां पर ज्यादातर लोग काम करते हैं, उनको बढ़ोतरी दी जाएगी, ताकि लोगों को रोजगार मिले। लोगों का जो वेतन है, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए, मैंने इस सरकार की बात मान ली कि देश आज बहुत तरक्की कर रहा है। यह भी मान लिया कि आज देश की जीडीपी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गयी है। हमने यह भी मान लिया कि आज हमारा देश पाँचवे नंबर पर है और कुछ सालों के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अगर सरकार के मंत्रियों की बात सुने तो देश की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है। इस सरकार से मेरा यही प्रश्न है कि अगर देश की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी है तो आज हमारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों नहीं घटे हैं? आज पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस घट चुकी है। आज हमारे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हम लगभग 40 देशों से तेल ले रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार रूस से चीप ऑयल ले रही है। जब हम चीप ऑयल ले रहे हैं, जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लायर्स हैं, तो हम यह पूरा का पूरा बेनिफिट कंज्यूमर को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम पहले की तरह 60 या 70 रुपये प्रति लीटर तेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर हमारी व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो मैं इस सरकार से गारंटी मांगूंगा कि आज इस साल हमने शुरुआत में जो इंफ्लेशन देखा, दूध के दामों में जो इंफ्लेशन देखा, टमाटर के दाम में जो इंफ्लेशन देखा, वह इस साल में नहीं होगा। अगर आज भी यह सरकार कह रही है कि इंफ्लेशन हो सकता है तो यह सरकार किस प्रकार का काम कर रही है? यह सरकार आज ग्राहकों के लिए काम नहीं कर पा रही है। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि यह सरकार चंद कंपनियों के लिए काम रही है।

महोदय, पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि देश की जो आर्थिक अवस्था है, वह ठीक नहीं हो रही है। यहां एक कार्टेलाइजेशन और मोनोपॉली बन रही है। अगर आप बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज सेक्टर में देखेंगे तो हर सेक्टर में तीन-चार बिजनेसमैन डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वह एविएशन हो, चाहे टेलिकॉम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे मेटल्स हो। यह कितनी अफसोस की बात है कि हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक ढांचा है, ऐसी कुछ कंपनीज हैं, जो डोमिनेट कर रही हैं, कार्टेलाइजेशन हो रहा है, मोनोपॉली हो रही है, उनके आधार पर चल रहा है। इसके कारण हमारे देश के जो आर्थिक रेगुलेटर्स हैं, वे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं।

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस ने कुछ कंपनियों को नोटिस भेजा था कि आप इंडोनेशिया से बहुत कम दाम पर कोयला लाते हैं और भारत में आकर उस दाम को बढ़ा देते हैं। यह क्यों हो रहा है, इसके लिए कागज मांगे थे, लेकिन आज तक उन विभिन्न कंपनीज़ ने अपने कागज डीआरआई को नहीं दिए। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की तहकीकात करने से डरती है? क्या यह बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने से डरती है? सुप्रीमकोर्ट को सेबी को कहना पड़ा कि आप एक विशेष कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करें। क्यों इस अवस्था तक हम पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा। यह बहुत अफसोस की बात है कि जहां पर हमें ग्राहकों को सुरक्षित करना है, किसानों को सुरक्षित करना है, श्रमिकों को सुरक्षित करना है, यह सरकार विशेष कंपनियों को सुरक्षित कर रही है। विशेष एक-दो कंपनीज़ हैं, जिनका नाम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बवाल मच जाएगा, क्योंकि सरकार आज देश की नहीं उस कंपनी की चल रही है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सरकार को देश हमारे श्रमिकों ने चुना, मजदूरों ने चुना, ट्रक ड्राइवर्स ने चुना, घर में काम करने वाले लोगों ने चुना, मैकेनिक्स ने चुना, क्राफ्ट्समैन ने चुना, दुकानदार ने चुना। आज हमें उनके लिए सोचना चाहिए। आज हम गिग इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन हम गिग वर्कर्स के लिए कौन सी सुरक्षा लाए हैं? कोविड के समय हमारे यहां आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भरपूर काम किया। आप डॉक्टर हैं। आप खुद जानते हैं कि आशाकर्मी हमारे देश में स्वास्थ्य का जनजागरण करने के लिए कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। आशाकर्मी, आंगनवाड़ीकर्मी आज हर प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं। उन्हें और भी मदद चाहिए, लेकिन आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आज भी हमें उन लेबर इंटेन्सिव इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान देना चाहिए। टी, कॉटन, रबर्स, स्पाइसेज़, विशेष रूप से मैं टी का उल्लेख करना चाहूंगा। असम, जहां से मैं आता हूं, हमारे यहां असम की चाय बहुत ही मशहूर है। लेकिन, विशेष रूप से नेपाल से जो हम चाय की पत्ती आयात कर रहे हैं, उससे असम टी का ब्रांड खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि नेपाल से इल्लिगल इंपोर्टेड टी का जो बिजनेस स्कैम चल रहा है, उसको आप बंद करें और हमारी असम की सीटीसी टी पर एक जीआई टैग लायें। आज एक ही चिंता हमारे मन में है। देश की जो आबादी है, वह युवा हो रही है, जबकि पूरी दुनिया में आबादी वृद्ध हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं को जिस प्रकार से शिक्षित होना चाहिए, उनके हाथ में जो कला होनी चाहिए, उनके हाथ में जो हुनर होना चाहिए, वह आज भी नहीं हो रहा है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, जितना लोगों को गेनफुल इंप्लायमेंट मिलना था, आज भी वह नहीं मिल रहा है। आज चाहे डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, नर्स हो, क्राफ्ट्समैन हो, होटल में काम करने वाला व्यक्ति हो, हमें स्किल ट्रेनिंग, स्किल एजुकेशन पर और ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री को उस हिसाब से शिक्षा पर, स्किल डेवलपमेंट पर और ध्यान देना चाहिए। यह बजट, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स सिर्फ कंपनीज़ का नहीं, सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का नहीं, यह आम जनता का होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, धन्यवाद । मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो वक्ता हैं, वे पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशन्स को कभी पढ़ते ही नहीं हैं। मैं लगातार 10 सालों से उनके वक्ताओं को सुन रहा हूं। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जब आता है, तो उसमें रूल साफ कहता है कि जिस विषय के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आया है, वक्ता केवल वही और वही बोल सकते हैं। किसी भी पॉलिसी डिजीजन के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है। मैंने जानबूझकर गौरव जी को नहीं रोका। कांग्रेस की जो स्थिति इन तीन राज्यों

में हार के बाद है, तो अगली बार कितने सांसद आएंगे, नहीं आएंगे, पता नहीं। कांग्रेस के जितने लोग बोलते हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नियम-कानून से इसका कोई मतलब नहीं।

दूसरा, जहां से उन्होंने बंद किया, वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। हमारे यहां एक कहावत है कि अपने दिल से जानिये, पराये दिल का हाल। सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1947 से लेकर 1991 तक, 54 सालों तक इस देश में लाइसेंस, परमिट और कोटाराज रहा। यदि किसी को कार बनानी है तो बिरला जी की एम्बेसडर के अलावा किसी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने देश में किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि बिरला जी उनके संसद सदस्य होते थे, कांग्रेस के पदाधिकारी होते थे, कांग्रेस के लोग होते थे। यदि स्कूटर बनाना है तो बजाज फैमिली ही बनाएगी। जमनालाल बजाज बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूं। यदि किसी को स्कूटर का लाइसेंस मिलेगा तो बजाज साहब को ही मिलेगा। यदि किसी को सीमेंट बनाना है, आपको रामकृष्ण डालमिया के बारे में पता है, अखबार भी रामकृष्ण डालमिया जी का परिवार चलाएगा। यदि सीमेंट की फैक्ट्री बनानी है या इंडस्ट्री बनानी है, टाटा, बिरला, डालमिया लाइसेंस परमिट कोटा राज में कांग्रेस आगे बढ़ी है, इसीलिए आज इस दौर में भी केवल बिजनेसमैन नजर आ रहे हैं।

मैं यह कह रहा हूं कि 5 जी का ऑक्शन हो रहा है, 4 जी ऑक्शन हो रहा है। किस कंपनी को भारत सरकार रोक रही है। मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि किस कंपनी को भारत सरकार कह रही है कि तुम टेलीकॉम में नहीं आओ। आज सीमेंट बनाने वाली 50 कंपनियां हैं, अहलुवालिया मेहर में भी बना रहा है, रामको इंडस्ट्री चेन्नई में बना रहा है। छोटे-छोटे लोग जिनके बारे में उनको पता नहीं है, वे सारे लोग सीमेंट इंडस्ट्री में हैं। यदि आज ईवी का चलन बढ़ रहा है, हम जिस तरह से इन्सेन्टिव दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हिकल या कार बनानी है या स्कूटर बनाना है, हमने एलन मस्क से कहा कि आपको हम सुविधा देंगे, बशर्ते आप हमारे यहां मैन्यूफ्रेक्चर कीजिए जिससे हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिले। क्या यह सब उनको दिखाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा कि यदि किसी ने आंख पर पट्टी बांध ली है तो हम क्या कर सकते हैं?

आज इस देश की इकोनॉमी के बारे में पूरी दुनिया कह रही है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जहां पर क्रेडिट था, जिस पर आप लोन देते हैं, लोन पहले एक परसेंट, दो परसेंट और तीन परसेंट पर मिल जाता था, आज वह लोन दस परसेंट पर मिल रहा है। दस परसेंट पर लोन मिल रहा है। आप बाइडन का स्टेटमेंट देख लीजिए या सुनक का स्टेटमेंट देख लीजिए। सारे लोग कहते हैं कि कोरोना के बाद हमने लोगों को फ्रीबीज दे दिया, इन्सेन्टिव दे दिया, इस तरह से हमने इकोनॉमी को तबाह कर दिया। आज इन्फ्लेशन का रेट पूरी दुनिया में 10 परसेंट से ऊपर है। सुनक और बाइडन का एक बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आया कि हम इनफ्लेशन को कम कर सकते हैं, इनफ्लेशन के बाद यदि बैंक डिसाइड करती है तो इंटरैस्ट रेट कम हो सकता है।

भारत ही एक ऐसा देश है जहां आज इंटरैस्ट रेट कम है। इनफ्लेशन हमने पांच परसेंट के आसपास रखा है, चीन की हालत खराब है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, जिसका भी उदाहरण लेना चाहते हैं सभी लोगों की स्थिति यह है कि लोग अपने मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। लोग अपने मकान की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। वहां की हेल्थ व्यवस्था सारी की सारी चौपट हो गई है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया आशा की नजरों से देख रही है, हमने इनफ्लेशन कंट्रोल करके रखा है, पांच परसेंट इन्फ्लेशन है, हमारी इकोनॉमी सात - साढ़े सात परसेंट जीडीपी ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। क्या यह आपको दिखाई नहीं देता, क्या इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को

धन्यवाद नहीं देना चाहिए। क्या इसके लिए देश को गौरान्वित नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे - कुछ नहीं हो रहा है। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है।

दो-तीन चीजें इकोनॉमी की बढ़ी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में हमने इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए कुछ पैसे का प्रावधान किया है। क्या प्रावधान किया है? जब इस देश में जीएसटी लागू हो रही थी तब कई लोग कह रहे थे कि राज्य का पैसा कम हो जाएगा, इकोनॉमी कम हो जाएगी, कलेक्शन कम हो जाएगा, उनका क्या होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितना कम होगा उतना कम्पनसेशन हम देंगे।

आप निश्चित रहिए, हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा। यह मनमोहन सिंह जी कहते थे कि जिस दिन इस देश में जीएसटी लागू हो जाएगा, उस दिन जीडीपी डेढ़ से दो परसेंट बढ़ जाएगी। आज क्या हाल है? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 1 लाख 61 हजार करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन प्रति माह हो रहा है जबकि पहले यह 80,000-90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होता था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि 17 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के लिए एक टार्गेट फिक्स करके रखा था कि 12 से 13 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन होगा जबकि यह आज 25 परसेंट ऊपर जाकर 16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसका कारण क्या है? हमने फेसलैस सिस्टम लागू किया, जीएसटी में टेक्नोलॉजी लागू की। पहले जितने भी चोर, बेईमान लोग थे, जो टैक्स नहीं देने की कोशिश करते थे, अब नौ करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं।

महोदय, हमने जब वर्ष 2014 में चार्ज लिया तो उस वक्त तीन या चार करोड़ लोग ही टैक्स पे करते थे। मैं कल ही जवाब दे रहा था कि देश में साढ़े नौ करोड़ लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी उसी हिसाब से बढ़ रही है। अब ये क्या कहेंगे? पेट्रोल और डीजल की बात ही तो कहेंगे। चूंकि ये राजस्थान में हार गए हैं, इस सवाल पर सारे सांसदों और पूरे देश की पोलिटिकल पार्टिज़ को सोचना चाहिए कि जीएसटी के दायरे में दो चीजें नहीं आई हैं। आप बार-बार ब्लेम भारत सरकार को देते हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम ज्यादा है और लोग परेशान हो रहे हैं।

महोदय, आपने जो दो चीजें छिपा रखी हैं, रोक रखी हैं, मैं उसका कारण समझ रहा हूँ। झारखंड में एक रेड चल रही है, कांग्रेस के बड़े सम्मानित सांसद हैं, तीन बार से सांसद हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, 500 करोड़ रुपये के आसपास कैश पकड़ा जा चुका है। आज संजय सेठ साहब ने इसे बड़ी प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया। इसका कारण क्या है? यह पैसा क्या है? मैंने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की स्टेटमेंट पढ़ी, वे कह रहे हैं कि उनका यह पुश्तैनी धंधा है, शराब के धंधे में हैं, शराब के धंधे का यह पैसा है। मैंने बड़े नेताओं की स्टेटमेंट पढ़ी है और मैं इसलिए सारे सांसदों और पोलिटिकल पार्टिज़ के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जीएसटी के दायरे में दो चीजें नहीं हैं और इन दो चीजों के कारण से भारत की इकोनॉमी में आम जनता निश्चित तौर से प्रभावित हो रही है। सभी कन्सेंसस बनाएं, भारत सरकार ने ऑफर किया है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आइए, लेकिन फिर आपको यह कहने का मौका मिलेगा कि भारत सरकार के कारण पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम घट रहे हैं। राजस्थान ही ऐसी सरकार थी, जहां पूरे देश में 12 या 13 रुपये ज्यादा महंगा था। आप पैसा कमाएं। यह तो रत्नाकर वाली बात हो गई कि रत्नाकर चोरी करके पूरे परिवार को चलाता था, लेकिन जब पाप लेने की बात आई तो पूरे परिवार में से कोई आदमी शामिल नहीं हुआ। आप पेट्रोल और डीजल में कमा रहे हैं, आपकी जो सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार खत्म हुई, चाहे

राजस्थान की सरकार हो, पेट्रोल-डीजल का ज्यादा पैसा लेती है और उसके बावजूद आप भारत सरकार को ब्लेम करते हैं।

महोदय, लिकर का पैसा जमा करते हैं, सांसद पकड़े गए हैं, आप लिकर को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? फिर आपको पता चलेगा कि जो दाम महाराष्ट्र में है, वही छत्तीसगढ़ में है, वही झारखंड में है और वही बिहार में है, खैर बिहार में तो शराबबंदी है। आप इन दोनों को दायरे में नहीं लाएंगे क्योंकि ये आपकी पैसा कमाने की मशीनें हैं।

महोदय, ये लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। आप बताएं कि किस माननीय प्रधान मंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपनी कोई सोच रखी है? जब माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री बने और उससे पहले जब वह गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे, तब सबसे बड़ा डिजास्टर कच्छ में हुआ था। सभापति जी, आप भी उसी राज्य से आते हैं। आपको ध्यान होगा कि कच्छ और सूरत, दो इंसीडेंट्स हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, जो आज के माननीय प्रधान मंत्री जी हैं, नरेन्द्र मोदी जी ही इस देश के पहले और एकमात्र प्रधान मंत्री हैं, जिन्हें गांव, गरीब और किसान की जान की चिंता है और वे वोट बैंक की पोलिटिक्स से ऊपर उठकर चिंता करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहली बार भारत सरकार इतनी आगे रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का बड़ा इश्यू था, आप देखें कि उत्तराखंड के 39 लेबर्स को बचाने के लिए कौन सा ऐसा देश है, जिसके थ्रू भारत सरकार ने प्रयास नहीं किया? चाहे आर्मी हो, एयर फोर्स हो, एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, कौन सी ऐसी संस्था थी जिसे भारत सरकार ने टच नहीं किया?

मैं इसीलिए इस बारे में बहुत इमोशनल हूँ कि हमारे यहां एक रोप-वे की दुर्घटना देवघर में हो गई, जिससे काफी जानें वहां फंस गई। एक-दो लोग मर गए और उसके बाद गरुड़ एयरफोर्स की गरुड़ बटालियन, जिसका काम केवल और केवल विदेश में जाकर दुश्मनों को मारना है, उस एयरफोर्स की सहायता से उन लोगों को बचाने के लिए देवघर रोप-वे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुद मॉनिटर करके सारे लोगों को बचवाया और इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। चाहे नेपाल में आपदा हो जाए, टर्की में आपदा हो जाए, चाहे हिमाचल प्रदेश की बाढ़ हो जाए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करते हुए प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जीत का जश्न तो मनाएं, लेकिन कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया कि अभी चेन्नई में बाढ़ आने वाली है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी उसका इम्पैक्ट होने वाला है। अतः भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया। इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी आग्रह करना चाहिए कि सब काम छोड़ो, डिजास्टर मैनेजमेंट में लगे। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया, जिसके कारण आज हम जान बचा पाने की स्थिति में हैं।

दूसरा, माननीय सदस्य नॉर्थ-ईस्ट से आते हैं। मैं नॉर्थ-ईस्ट में वर्ष 2014 से पहले भी गया था। अभी कांग्रेस के स्पीकर नॉर्थ-ईस्ट के बारे में बोल रहे थे। नॉर्थ-ईस्ट की क्या स्थिति थी? नॉर्थ-ईस्ट की स्थिति यह थी कि वहां जाने के लिए कनेक्टिविटी नहीं थी। आज त्रिपुरा तक रेल जा रही है, आज अरुणाचल प्रदेश तक रेल जा रही है। असम से आपको कनेक्ट करना था, जो केवल एक पुल के कारण रुका हुआ था, वहां अब इंडस्ट्री जा रही है। मैं सिक्किम गया था। वहां जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, शायद भारत में पुणे और हिमाचल प्रदेश के बद्दी को छोड़कर किसी और जगह पर उतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नॉर्थ-ईस्ट के लोग अब यहां नहीं आना चाहते? चाहे नॉर्थ-ईस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल हो, डेवलपमेंट का सवाल हो, बॉर्डर के ऊपर अंतिम गांव तक रोड बनाने का सवाल हो, वर्ष 2014 से पहले क्या स्थिति थी, आप बताइए। यदि वर्ष 2014 से पहले लोगों को गुवाहाटी से शिलांग जाना होता था, तो कितने घंटे लगते थे? आप वर्ष 1972-73

की बात कीजिए। आज शिलांग जाने में मुश्किल से एक-डेढ़ घंटा लगता है। शिलांग, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एयरपोर्ट्स आ गए हैं। आपने क्या किया? सब जगह ट्रेन भी पहुंच गई। आप कह रहे हैं कि नॉर्थ-ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया।

महोदय, नॉर्थ-ईस्ट ही नहीं, ईस्टर्न इंडिया, जिस इलाके से मैं आता हूं, गोड्डा, जहां से मैं सांसद हूं, वहां आजादी के 75 साल बाद भी रेल लाइन नहीं थी। संयोग से मुंडा जी यहां दिखाई दे रहे थे। वह मुख्य मंत्री के नाते वहां शिलान्यास करने गए थे। वहां यदि आपका एक मामूली एक्सिडेंट हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो उसके लिए एक डॉक्टर या अस्पताल नहीं था, एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन नहीं था, जहां आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएं। यद्यपि रामकृष्ण मिशन ने एक अच्छा स्कूल बनाया था, जिसे 100 साल हो गए हैं। आज वहां मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी संस्था है, एयरपोर्ट है। आज गंगा नदी पर वाटर वेज है। केवल बंदरगाह समुद्र में ही नहीं खुल रहा है, साहबगंज में हमारे यहां गंगा पर बंदरगाह है, जिससे माल-ढुलाई का काम हो पाए, जिससे नेपाल को हम सप्लाई कर पाएं, जिससे भूटान को हम सप्लाई कर पाएं। जिस चार लेन का रोड लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा था, वह चार लेन का रोड ईस्टर्न इंडिया में इतनी छोटी जगह पर दिखाई दे रहा है। चाहे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, भारत सरकार की कोई ऐसी संस्था नहीं है, जो वहां मौजूद न हो। ट्राइबल के लिए हम जाने जाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 नवम्बर को जिसका काम किया। आपको जानना चाहिए कि सिकल एनीमिया नामक एक बीमारी ट्राइबल्स में होती है, जिसके कारण वर्षों से ट्राइबल्स परेशान रहते थे, इस हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी ने देवगढ़ एम्स को डेडीकेटेड सिकल एनीमिया का एक सेंटर बना दिया, जिससे कि हम ट्राइबल्स के बच्चों को इस तरह की बीमारी से बचा पाएं। उस दिन मैंने कहा था 100 परसेंट प्रधान मंत्री आवास सभी लोगों को मिलेगा। मैं मोटर साइकिल से जाते हुए गिर गया था, जिससे मुझे घाव हुआ था। आज भी वहां के लोगों हेतु न प्रधान मंत्री आवास है, न पीने का पानी है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, यानी कुछ भी नहीं है।

प्रधानमंत्री जी ने 15 नवम्बर को एक प्रोजेक्ट ?प्रधान मंत्री जनमन? चालू किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 100 परसेंट, कोई भी ट्राइबल होगा, उसको हम मकाने बनाने के लिए 2 लाख 30 हजार रुपये देंगे। कोई ऐसा गाँव नहीं है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड नहीं जाएगा और कोई ऐसा घर नहीं है, जहां ? प्रधानमंत्री नल जल योजना? से पानी नहीं जाएगी। यह किसने सोचा? आप ट्राइबल का वोट लेते रहे और आप कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं।

सर, इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में तीसरा सवाल फर्टिलाइजर का है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में एक बड़ा सवाल है। यह सभी को पता है कि फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे वह यूरिया बनाने के लिए हो, डीएपी बनाने के लिए हो, नाइट्रेट बनाने के लिए हो या फॉस्फेट बनाने के लिए हो, कोई भी रॉ मटेरियल भारत में नहीं है। यह आज का तो सवाल नहीं है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। वाई.वी.चव्हाण, जो एक बहुत बड़े नेता थे, मैंने उनका वित्त मंत्री के नाते काफी बजट भाषण सुने हैं। वे वर्ष 1975-76 तक एक ही चीज चिल्लाते रहे कि मैं ऐसा बदनसीब वित्त मंत्री हूं, जिसको लोगों को खिलाने के लिए बाहर से अनाज लाना पड़ता है। हमें इसके लिए अपने किसान को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आज किसान सशक्त है। हमें बाहर से अनाज नहीं लाना पड़ता है। लेकिन, जब रॉ मटेरियल नहीं था, उस समय जब फर्टिलाइजर की जरूरत थी, क्या कांग्रेस के समय भारत सरकार ने कभी यह सोचा कि हमें फर्टिलाइजर में कैसे सस्टेन करना है? पूरी दुनिया में माइन्स के ऑक्शन हो रहे थे, जॉर्डन में हो रहे थे, मोरक्को में हो रहे थे, पांच-सात देश ही ऐसे हैं, जहां फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। क्या आपने कभी उनके साथ टाई-अप करने की कोशिश की? आज भारत पहला ऐसा देश है, जिसने फर्टिलाइजर पर और खासकर इसके ऊपर निर्भरता कम करने के लिए, ताकि

अपनी जमीन खराब न हो, सॉयल खराब न हो, उसके लिए ऑर्गेनिक फॉर्मिंग की तरफ बढ़ावा देने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग किया। भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह गर्व है कि उसने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा काम किया। आपके यहां गुजरात, कलोल में यूरिया और डीएपी का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहां देवघर में भी नैनो यूरिया का प्लांट बन रहा है और डीएपी का बनने वाला है। 50 किलो का बोरा, जिसको किसान अपने माथे पर ढोता था, अब 500 मिलिलीटर में उपलब्ध है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाई गई है, मैं आपको यह बता सकता हूँ कि जिस तरह से हरित क्रांति लाकर यह देश आत्मनिर्भर हुआ, उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमो ड्रोन दीदी? का जो कांसेप्ट है, उससे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वर्षों-वर्षों तक इतिहास याद रखेगा और उनको सम्मान देगा। किसानों की निर्भरता दूसरे चीजों पर कम होगी और उनकी किसानी का काम आगे बढ़ेगा, वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस कारण से तब तक, जब तक कि ये नैनो यूरिया और डीएपी में भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, ये फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि किसानों का जो लागत मूल्य है, वह ज्यादा न बढ़े। 80 करोड़ लोगों को, जिनको हमें खाना वर्ष 2028 तक देना है, कई लोग कहते हैं तो यदि इकोनॉमी बढ़ रही है तो आप क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन यह है कि मान लीजिए हम छोटे शहर में रहते हैं और अपने घर में रहते हैं। यदि हम अपने घर में 10 कट्टा जमीन में सब्जी पैदा कर लेते हैं तो हमें घर का किराया नहीं देना पड़ता है और सब्जी का भी पैसा नहीं देना पड़ता है। जो पैसा है, हम उसको बचत करते हैं। 80-81 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाज देने का फैसला किया है, उसका कारण यह है कि आपको जहां नौकरी करनी है, वहां कीजिए, आपको अपने जीवन में जितना व्यापार करना है, आप कीजिए, आपके बच्चे को जहां पढ़ना-लिखना है, आप वहां पढ़ाइए-लिखाइए, लेकिन आप खाने के बारे में आत्मनिर्भर रहिए। खाना की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, माननीय मोदी जी का है। यह मोदी गारंटी है। ? (व्यवधान) इसका कारण यह नहीं है कि भारत कहीं गरीब हो रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि वे लोग गरीब हैं। हमने उज्ज्वला गैस दे दिया, उससे क्या हो गया? अभी हमने सैचुरेशन पाइंट पर कहा कि जिसके पास उज्ज्वला गैस नहीं है, उसको उज्ज्वला गैस दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत सरकार उससे भी आगे बढ़ गई है। अब पाइपलाइन से गैस जाएगा। जो शहरों में स्थितियां थीं, वह आज हम गाँव में भी क्रिएट कर रहे हैं।

आज गांवों में लोग नल से जल पीते हैं। आज भारत में प्रत्येक परिवार ऐसा है, हम उनके पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? गांवों में विस्थापन और पलायन एक बड़ा विषय है, इस पार्लियामेंट में उस दर्द को बहुत कम लोग समझ पाएंगे, लेकिन झारखंड, बिहार और पूरे पूर्वोत्तर के जो लोग हैं, हम सबसे ज्यादा उसको समझ सकते हैं। मैं बार-बार ये बातें कहता हूँ कि मुंबई के लोग अपने आपको कहते हैं कि हम बहुत इन्कम टैक्स देते हैं। जब हम लोग मुंबई में नौकरी करने या रोजगार के लिए जाते हैं, तो वे भैया या बिहारी कहते हैं। आप यह समझिए कि भैया और बिहारी गाली है।

क्या कभी सोचा है कि मुंबई में जो टैक्सपेयर्स हैं, वे कौन लोग हैं? वे लोग वही हैं, क्योंकि इस देश का 50 प्रतिशत माइन्स और मिनरल्स केवल और केवल झारखंड देता है। चाहे टाटा की बात कर लीजिए, चाहे बिरला की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, यदि झारखंड नहीं होता, छत्तीसगढ़ नहीं होता, ओडिशा नहीं होता, पश्चिम बंगाल नहीं होता, चाहे कोयले का सवाल हो, चाहे माइन्स का सवाल हो, चाहे मिनरल्स का सवाल हो, वह सब हमने दिया है। हम जो मालिक थे, जिसने मुंबई को मुंबई बनाया है। आज आप हमको गाली देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी विस्थापन और पलायन को रोकने के लिए इस तरह का

कार्यक्रम किया है। यदि हम गांवों में ही सारी सुविधाएं दे देंगे, तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को इसका फायदा होगा।

महोदय, मुझे पता है कि और भी सदस्यों को बोलना है। चाहे एजुकेशन का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे जीआर का सवाल हो, चाहे बच्चियों को पढ़ाने का सवाल हो, चाहे उनको रोजगार देने का सवाल हो, आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीने रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। हम रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सरकार ने पिछले दस सालों में जो किया है, वह ?न भूतो और न भविष्यति?। तैत्तिरीयोपनिषद का एक श्लोक है -

?सर्वज्ञम् विज्ञातः सर्वयौनीस्तव मात्वभू, सर्व प्रभुर निश मेकस्त्वं सर्वरूप भाक?।

महोदय, इस हाउस में जितने लोग बैठे हुए हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का योगदान पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए राम-राम और जो स्वीकार करना चाहते हैं, उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. I would like to focus on the points like employment crisis, devolution of tax revenue from the Centre, agrarian crisis, precarious conditions that the public sector banks are facing, textile crisis, and the issues and problems in the MSME sector.

Sir, the employment status in India is showing an unprecedented fall in the total employment from 2014 to 2022. About 50 million jobs were lost due to multiple reasons. The three major reasons are Demonetisation, GST implementation, and COVID-19 pandemic. It is unfortunate that the total unemployed youth population is rising massively. The increased trend of contractual employment in both Government and private sectors is another threat to the economic security and peace. If this trend continues for another five years, there will be a great chaos all over the country. This is a red alert for the Union Government and also for the State Governments. The society and the parents have to pay heavily for this catastrophe. It is a ticking time-bomb which needs to be solved diligently. The Union Government which promised to create two crore new jobs every year is awfully short of the target. What is more dangerous is that they are trying to destroy the existing jobs in the Government sector and the PSUs. It is expecting that the private sector will create more jobs. But due to the economic crisis, the

private sector is falling like nine pins. Unfortunately, no concrete steps have been taken to create new jobs at all.

Sir, there are 40 lakh job vacancies in the Central Government, State Governments, and the PSUs across the country. If the Government cannot take any proactive measures to provide Government jobs to our youth population, a big catastrophe is waiting. The unemployment rate is at an all-time high of 10.3 per cent. For the age group of 18 and 26, it is 30 per cent. That means, about one-third of the youth of our country is unemployed and another one-third is under-employed. This is a ticking time bomb.

Sir, the second point relates to devolution of taxes. Tamil Nadu continues to be one of the largest contributors to the country's direct tax revenues. The Union Government is betraying Tamil Nadu on many counts, including devolution of tax revenue with data. As regards devolution of share of tax revenue, Tamil Nadu is not getting its due share. For example, for every one rupee that Tamil Nadu gives to the Centre, it gets back 29 paise, and incidentally, all the BJP-ruled States or their electorally prospective States are getting a lion's share. This is unjustifiable.

During the past 10 years, as per the Central Finance Commission's recommendations, Tamil Nadu has been facing huge financial losses. The allocation, which stood at 5.305 per cent in the Twelfth Finance Commission, has come down to 4.079 per cent in the Fifteenth Finance Commission. This is because Tamil Nadu implemented the Family Planning Scheme sincerely. The State is being betrayed in financial allocations in many other schemes too.

When compared to the amount Tamil Nadu is giving to the Union Government as tax revenue, it is receiving back a very less amount. The Union Government has offered the State nothing but only the State's tax share. Tamil Nadu is providing 9.16 per cent of the GDP to the Centre but the Union Government shared only 6.07 per cent of tax revenue to Tamil Nadu. Tamil Nadu has contributed Rs.5.16 lakh crore to the country's direct tax revenue but in return the State received only Rs.2.08 lakh crore. Tamil Nadu is facing a financial crisis.

When the DMK Government came to power, our hon. Chief Minister as well as our General Secretary of the Party and our hon. leader, Mr. T.R. Baalu visited the hon. Prime Minister. At the first instance, our General Secretary took the liberty of the Chief Minister and explained to the Prime Minister in the first meeting and said, ? The heat and the dust of the election is over. Mr. Prime Minister, now we are here

to extend our heart and hands in the vision to build this nation.? These were the words uttered by our General Secretary to the Prime Minister. In spite of that, still the big brother attitude of the Government of India is continuing in respect of Tamil Nadu.

Regarding the banks, it is disheartening to see the performance of the public sector banks. Their performance is very much wanting. Most of them are sinking very fast. The RBI's Report of 2023 has reported that in 2020-21, there were 7338 frauds amounting to nearly about Rs.1,32,000 crore and in 2021-22, there were 9097 frauds and the amount was around Rs.59,000 crore. In 2022-23, it was peaking; it was higher.

Six of the 11 banks do not even have the non-executive Chairmen, reported *The Wire* on 22nd June, 2023. Even the SBI has no such post. Over one-third of the PSB Director posts numbering 64 are vacant as on 12th January, 2023. The RBI Governor has recently said that the quality of the Directors is not up to the mark. Since 2014, none of the 12 banks have Employee and Officer Directors which are mandated by the law. This is in spite of the Delhi High Court's directive. Still the Union Government is not heeding to it.

The MSME segment, which is the largest provider of employment, is in crisis. Only the large corporates are favoured by the Government, and the smaller MSME segments are ignored. The loan facilities are not extended to them. The banks will be under serious trouble because of the amounts they have written off and the kind of NPAs they are having. Sir, 599 corporate companies with loans of about Rs.100 crore get a loan at less than five per cent interest whereas a poor education loan borrower pays 11-12 per cent interest. So, do the MSME borrowers. Why is this anomaly? Sir, 30 per cent of the bank loans have been shifted to the non-banking finance companies which get loans from the banks at 10-11 per cent and lend at the rates of 36 per cent. Now even the ceiling has been lifted. If this is the case, if this continues, then the banking sector has to be looked upon, and both the Union Government and the Finance Minister have to pay attention to the banking sector.

My next point is about the GST. The GST has disturbed the small businesses and damaged the erstwhile sales tax system abruptly. Several lakh companies just could not cope up with the haphazard imposition of GST and the implication of the GST *raj*. The MSME sector took a big battering first by the demonetization and then by the haphazard imposition of GST.

Sir, 100 per cent guarantee at a concessional rate of 9.25 per cent for the MSMEs under the ECLG Scheme with an overall ceiling of Rs.3 lakh crore was the second biggest component out of the overall Rs.20 lakh crore package announced in 2020 but nothing has happened. We heard only slogans like 'ease of doing business?', 'one crore loan in 59 minutes?'. They are all slogans.

Sir, the Finance Minister had prodded public sector banks to expeditiously ensure easier flow of credit to micro, small and medium enterprises, and asked them to simplify the processes. But bankers never heeded to the Finance Ministry, and still if a common man wants to get a loan, he has to face a lot of hardship.

There is a need for quick disbursement of additional loans to MSME segment. Hence, they urged bankers to simplify process, formats and documentation. But at the ground level it is very different. The banks ask too many questions and lay too many conditions, and finally reject the loan proposal. This happens to 99 per cent of SMBs out of 100. The Government should take a serious note of it and act accordingly.

Currently, the rate of interest on loans given by banks to MSMEs varies from 9.5 per cent to 17 per cent depending on the risk perceptions. But no one is getting loans with 9.5 per cent interest. It normally goes up to 14 to 15 per cent and even to 17 per cent also. This again is a trap and literally unviable for anyone to stabilize their business.

Sir, now let me talk about my State of Tamil Nadu. Our great Dravidian leaders Thanthai Periyar, Peraiyinar Anna and Muthamilarignar Dr. Kalaignar and our beloved Chief Minister M.K. Stalin have trained us to conquer the conqueror. Our Chief Minister, Thiru M.K. Stalin has evolved a new political theory for the entire Indian nation called 'The Dravidian Model of Administration'.

Sir, a Dravidian Model means, the face of a Dravidian government is not power, but love; not arrogance, but democracy; not ornamentation, but simplicity; not totalitarianism, but equality; not fanaticism, but social justice. That is why it is criticised by a few but loved and now followed by many States in India. The Dravidian model cannot be subjugated.

Sir, textile industry is a sunshine sector. There has been an increase in investments from International and domestic companies in Tamil Nadu. Our hon. Chief Minister called upon Japanese industrialists to expand their investments in the State and invest in infrastructure projects.

Sir, I would like to tell the House that six Memoranda of Understanding were signed between Tamil Nadu and Japanese companies towards investments to the tune of Rs.3818 crores in the State. Out of 82 projects, investment of Rs.52,549 crore is expected, which would provide employment opportunities to 92,000 people but the Finance Ministry is not even looking at the textile industry in Tamil Nadu. A number of projects are coming up in 22 districts across the State of Tamil Nadu. A new textile park has been developed in Tamil Nadu. A new textile policy has evolved in the State of Tamil Nadu. But the Union Government is not caring about anything.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: I am concluding it, Sir.

Sir, the issue of MGNREGS is a very important issue. As per the reply given by the Government in Lok Sabha on 5th December, 2023, the Government had stated that about Rs.2000 crores are pending as wage liability to States and Rs.4000 crores are pending as material liability as of 5th December, 2023. The Government in its supplementary demands is asking for Rs.16,142 crores as additional grants. Sir, in view of the above, there are three questions that I want to ask to the Government. Presently, there is a total pending liability of Rs.6000 crore, and about four months of work is pending under MGNREGS. How does the Government plan to manage these demands with a small allocation of Rs.16,142 crores? How much of the allocated budget of Rs.60,000 for MGNREGS has been spent so far? Finally, the revised estimates would be Rs.76,000 crores for MGNREGS which would be 16.6% less than the 2022-23 RE of Rs.89,400 crores last year. When the number of active beneficiaries for the scheme is more than that of 2022-23, then why does the Revised Estimate allocation is less compared to the last year?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, I am concluding in two minutes. I am the only member from my party to participate in this discussion.

Sir, I belong to Vellore constituency, and I have got three major points which I want to discuss in this budget. Kindly give me an opportunity to continue.

Sir, we are talking about Swachh Bharat. The Government of India is spending too much money on Swachh Bharat Mission in all over India. But Swachh Bharat Mission does not include only clean city mission, even sanitation also comes under

it. I belong to Vellore and it is a big Municipal Corporation. It is a land of mutiny where the struggle for independence started. I asked the Government many a time in this august House for a waste management project. Many proposals have been given to the Government of India. But nothing has happened in this budget. When we talk about development, NHAI is a very big organization in the Government of India.

15.00 hrs

Sir, nearly four years are over. The Government had announced major roads. One such major road, I would like to submit in this august House, is from Chennai to Bengaluru, which is a big corridor. Our hon. Minister, Shri Nitin Gadkari ji also talked about this many times in this Parliament.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, it is a very important matter.

Sir, the money has been given, the tender has been floated, but the work has not been completed. The NHAI contractors in Tamil Nadu are not heeding to the Government at all.

In my constituency, there are four bridges, which include Kandaneri-Vettuvanam, Ambur-Reddythoppu and Ambur New Town bridge, for which the funds have been allocated, but nothing has happened.

Sir, I will end by saying one single line. I would like to tell this august House and the Union Government one Thirukkural verse:

?Idipbaarai illaa yemaraa mannan

keduppaar ilaanum kedum?

This means ?The king, leader or businessman, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him.?

Thank you.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants. I would have been happy if the Finance Minister was here. The whole House looks like a desert. The Finance Minister is not there. Out of the two Ministers of State, only one is there. One Minister for Tribal Affairs is there. The

Law Minister is also there. The others have all escaped. What is the point of speaking, if the Ruling Party does not stay?

Anyway, the Government is going to enhance its spending by a little over Rs. 58,000 crore, with about one-third of this being allocated to subsidies. Gross additional expenditure met by savings of the Ministries and Departments and by enhanced receipts is Rs. 70,000 crore. Additional Rs. 14,524 crore have been given for MGNREGS. This would take total MGNREGS bill to Rs. 77,175 crore, which is lower than Rs. 89,150 crore last year.

Regarding MGNREGS, I am saying that this Union Government is being cruel to West Bengal. It has deprived us of Rs. 7,300 crore. People who have worked for MGNREGS are being deprived of their wages. I have never heard of such a Government here. They will have to pay for this cruelty to West Bengal farmers. The Chief Minister has said yesterday that total dues from the Centre amount to Rs. 1,15,000 crore. The Chief Minister will be coming next year to make her demand to the Prime Minister and other Central Ministers. I demand in this House that West Bengal dues be paid.

Having said that, I will say a few words about the economic situation. The Finance Minister in her Rajya Sabha speech said that the Centre has addressed the issues of inflation, unemployment and inequality. I shall take them up one by one.

Let me say that the Centre is confident of achieving fiscal deficit target of 5.9 per cent and is committed to lowering the fiscal deficit to 4.5 per cent in two years. Now, let us look at the Budget. *The Economist* of London says that sluggish investment is holding India back. Investment as part of GDP was 40 per cent in 2008 and is now 34 per cent. The money is not going into factories, research and private business, rather in infrastructure funded by the Government.

As a result of this, Foreign Direct Investment, FDI, fell by 16 per cent to \$71 billion in the fiscal year ending March 31st, 2023. FDI is falling. Finance Minister said that all is right in the State of Denmark. Out of the \$120 billion worth of projects scheduled to be completed by 2023, only \$72 billion worth of projects were finished. This is the condition of infrastructure.

I came across an article by Eswar Prasad, Cornell Professor. He said: 'The country's infrastructure has many gaps in supporting a vibrant manufacturing sector. The educational sector is not equipping young people with the vocational and educational skills needed for a modern economy.' Job growth has been weak with

little net employment creation in the manufacturing and service sectors. This raises fears of social instability. People go unemployed, society will be disturbed. Professor Prasad says: "Endemic corruption continues to hold back business dynamism as politically well-connected conglomerates have accounted for significant share of growth leading to a concentration of economic power." A well-functioning legal system, a free Press, and other checks and balances are key to maintaining investors' confidence. This Government has been prickly about criticism. So, this has held back investment. अगर लोगों को चिंता रहती है कि सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा, तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई पड़ जाएंगे, तो कोई यहां आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा।

Now, I am reading *Financial Times*, which is the most respected economic journal in the world. What do they say about Indian economy? We are talking about stock market. They say: "Indian upper middle class that invests in the local stock market accounts for three per cent. In China, it is 13 per cent. It is 55 per cent in USA. So, a very low percentage of people invest in the stock market. The benefits of India's growth have been distributed shockingly unequally. Whereas its share of GDP going to the top one per cent grew in China between the 1980s and the 2010s from seven per cent to 13 per cent, in India, it rose from 10 per cent to 22 per cent. So, inequality is there. India today is more unequal than even post-apartheid South Africa and Putin's Russia." (व्यवधान) क्या है

I am not saying this. This is *Financial Times*. (Interruptions) Uday ji, you are one of the persons who read a few business magazines.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, रूल 216 कहता है कि : "The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying..." ये वही सारे बोल रहे हैं। सर, आप इनको डिमांड फोर ग्रांट्स पर बोलने के लिए कहिए। (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, now, when we talk about stock markets, who is the biggest beneficiary of stock market? (Interruptions) प्रॉब्लम क्या है?

HON. CHAIRPERSON: You confine it to demands for grants.

PROF. SOUGATA RAY: The *Financial Times* says the biggest beneficiary of stock market is ? I am not saying this ? whose connection with ? goes back to the aftermath of Gujarat riots. (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Don't speak such words.

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Remove these words. It will not go into the records.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It will not go into the records.

? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, ऐसा नहीं है।(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप आगे बढ़िए।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह केवल डिमांड फोर ग्रंट्स पर बोलेंगे। यह गलत है।(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, ?and ? are ? partners in nation building. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : फिर, सर।

HON. CHAIRPERSON: It will not go into the records. Do not speak it.

? (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, ? and ? are ?partners in ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: What he is saying will not go in the record.

? (*Interruptions*)?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, ये क्या कर रहे हैं? माइक में ऐसे कुछ भी बोल देंगे। ऐसे थोड़े ही होगा।? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैंने किसी का नाम नहीं बोला।? (व्यवधान) ? and ? are ? partners in nation-building. ? (*Interruptions*) But they are not globally competitive ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

? (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, ? are not globally competitive entrepreneurs. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Why are you repeating?

? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It will not go in the record.

? (Interruptions)?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, in 1980, India lost out to China in manufacturing. What is happening in India is that in 2020 World Bank's Human Capital Index, which measures education and health outcomes, India had a score of 0.49 that is well below Nepal and Kenya, which are both poor countries. China had a score of 0.65. Since 1990, Indian women's labour participation has fallen from 32 per cent to 25 per cent. There are hundreds of millions of unemployed and unskilled youth. The biggest problem today is unemployment and this is borne out by the World Bank Report. ? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now.

? (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, why are you not giving me time to speak?

HON. CHAIRPERSON: No, you have been given enough time.

? (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, Nishikant ji went on speaking. You kept quiet. ? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, there is no question of keeping quiet.

? (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You have been given enough time.

? (Interruptions)

प्रो. सौगत राय : सर, आप मेरी बात सुनिये।

HON. CHAIRPERSON: Now, you conclude your speech.

? (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, unemployment among under 25 is already more than 45 per cent. Despite progress in many matrices, a substantive welfare state remains an illusion.

I want to say that in per-capita GDP index out of 194 nations, we are at 133. From 2014 to 2023, the price of rice has risen by 56 per cent, wheat by 59 per cent and milk by 61 per cent. Impact on growth is not being felt on the ground. Literacy is only 74 per cent. Unemployment rate for 15-24 years is 23 per cent, and for graduates it is 42 per cent. देश की हालत के बारे में सुनिये। All is not well in the state of ? (*Interruptions*). India has 23 crore poor people, and among children 16.3 per cent are under-nourished. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Sougata Ray ji, kindly conclude now.

? (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, according to McKinsey, India needs to boost its rate of employment growth and get 90 million non-farm jobs per year between 2023 and 2030 to increase economic growth. The net employment rate needs to grow by 1.5 per cent per annum. ? (*Interruptions*)

This is neither an economic recovery nor is it a growth-oriented economy. It is an economy which benefits only the ? and ?? (*Interruptions*) Thank you, Sir.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपनी बात रख रहा हूँ। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 58 हजार 378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए लोकसभा में ये अनुपूरक मांगें पेश की हैं और एक लाख 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय इस अनुपूरक मांगों में शामिल की हैं। इस अतिरिक्त खर्च में उर्वरक सब्सिडी का करीब 13 हजार 351 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है।

महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व में 7 वें स्थान पर है। जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा था, किन्तु वर्ष 2023 के मध्य से हम प्रथम स्थान पर हैं और केवल 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17.76 प्रतिशत भाग को शरण प्रदान करता है।

वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों के आधार पर विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2005 में यह 10 वें स्थान पर थी।

साल 2014 से मौजूदा साल 2023 तक देश का आर्थिक सफर ऐसा रहा है, जिसे रोलर कोस्टर राइड कह सकते हैं। कोविड के संकटकाल से जूझती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था की

हालत भी डगमगाई थी, जबकि आज कोविड के संकटकाल से बाहर आकर भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यह वास्तव में हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और यह माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में ही संभव हुआ है।

महोदय, जब वर्ष 2014 में केन्द्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई तो वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा 2.6 फीसदी पर था। आज इसे देखें तो यह बढ़कर 3.5 फीसदी पर आ चुका है। आजादी के 75 वें साल में यह आंकड़ा देश का हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक देश के जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। महोदय, अभी देश ने आर्थिक मोर्चे पर काफी शानदार मुकाम हासिल किया है और ग्लोबल चुनौतीपूर्ण माहौल में भी यहाँ आर्थिक विकास थमा नहीं है। देश भर में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। देश के हर गाँव, कस्बे को सड़कों और रेलमार्गों से जोड़ा जा रहा है। प्रतिदिन सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी बन रहा है।

महोदय, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने में अक्सर देरी होती है, जिसके कारण लागत में वृद्धि होती है, जिसका बजटीय आवश्यकताओं के साथ-साथ संचालन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में वर्ष 2017 में पुणे से लोनावाला तक तीसरे और चौथे ट्रैक को बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन 1600 करोड़ रुपये का बजट अभी 2,700 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने महारेल की स्थापना की है। उसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार ने समुचित सहमति दी है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड ने अगर मंजूरी दी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और रेलवे विभाग द्वारा तीसरे और चौथे ट्रैक, जो महत्वपूर्ण है, पुणे और मुम्बई को जोड़ने वाला, वह पूर्ण हो सकता है। मैं इन अनुदानों की मांग के तहत यह भी मांग करता हूँ कि इस तीसरे और चौथे ट्रैक को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।

महोदय, देश के हर गाँव को सड़क से जोड़ा जाए और देश को विश्वस्तरीय सड़क प्रदान हो, यह सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इस सपने को पूरा करने का कार्य माननीय गडकरी जी कर रहे हैं। आज प्रतिदिन 20 किलोमीटर से अधिक रिकॉर्ड सड़क निर्माण कार्य माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। महोदय, वर्ष 2023-24 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कुल खर्च 2,70,435 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 25 प्रतिशत अधिक है। सबसे अधिक व्यय एनएचएआई के लिए किया गया है। वर्ष 2023-24 में एनएचएआई को 1,62,207 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2013 तक देश में 90 प्रतिशत यात्री यातायात और 67 प्रतिशत माल यातायात सड़क नेटवर्क से किया गया था। भारतीय सड़कों के नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें और परियोजना सड़कें शामिल हैं। मार्च 2019 तक सभी सड़कों में 71 प्रतिशत ग्रामीण सड़कें थीं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 प्रतिशत थे। इसके अलावा जिला सड़कें 10 प्रतिशत और शहरी सड़कें 9 प्रतिशत हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में ऐसी सड़कें शामिल हैं, जो प्रमुख बंदरगाहों, पड़ोसी देशों, राज्यों की राजधानियों और व्यवहार कौशल आधार पर जरूरी सड़कों को जोड़ती हैं।

सभापति जी, मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में 13 हजार किलोमीटर के निर्माण की परिकल्पना की है। वर्ष 2023-24 में अक्टूबर तक 4474 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है जबकि पिछले वित्त वर्ष में अक्टूबर तक यह आंकड़ा 4060 किलोमीटर का था। परिवहन के सामूहिक विकास के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अक्टूबर, 2021 में लांच किया गया था। इससे आर्थिक विकास, बेहतर व्यापार प्रतिस्पर्धा, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में मदद मिल रही है।

महोदय, मंत्रालय शहरी क्षेत्रों प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), देश भर में 100 स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जैसी योजनाएं चलाकर देश को विकास की ओर अग्रसर करने का कार्य कर रहा है। महोदय, महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र सरकार किसानों की मदद कर रही है लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि महाराष्ट्र सरकार को किसानों की मदद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत ?हर घर जल? योजना में और भी अधिक सहायता की आवश्यकता है। नदी सुधार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत नदियों के पानी को साफ और स्वच्छ बनाने की योजना यदि चलाई जाती तो नदियां दूषित न होतीं। अभी पीने के पानी के साथ नदियों का दूषित पानी मिल जाता है और इस पानी को पीने से देश में कैंसर रोगी बढ़ रहे हैं। मेरी मांग है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को और अधिक प्रोत्साहन देकर सभी राज्य सरकारों के साथ एक बैठक कर नदियों के दूषित पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शुद्ध किया जाए और इस विषय पर एक ठोस कानून बनाकर राज्यों के साथ भागीदारी कर नदियों को साफ और स्वच्छ बनाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को विविध योजनाओं के पैकेज का पैसा समय पर नहीं मिला, जैसे कि जीएसटी का हिस्सा भी राज्य सरकार को समय से नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से महाराष्ट्र राज्य को अतिरिक्त या एक स्पेशल आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग करता हूँ जिससे कि जो भी परियोजनाएं किसी कारणवश आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में रुकी हुई हैं, उस राशि से उन परियोजनाओं को पूरा किया जा सके और राज्य के निवासियों के साथ ही साथ देश के अन्य नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

महोदय, इसी के साथ मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, thank you for allowing me to speak on the Supplementary Demands for Grants.

The Government is asking for an extra funding to the tune of Rs. 58,378 crore. A majority of this amount is going like this: an amount of Rs. 13,000 crore for fertilizers, Rs. 14000 crore for MGNREGA, Rs. 5,000 crore for food subsidy, and cylinder subsidy is Rs. 8,500 crore. It comes to a total of around Rs. 40,000 crore, which means 70 per cent of this expenditure is going towards rural economy, towards farmers, towards middle class people. This is not something new that is happening. The same thing has been happening for the last so many years, or at least for the four years when I am here. Every time we come to the Supplementary Demands for Grants. They keep asking money under these heads, and they keep getting funds under these heads. But somehow the rural economy is not moving anywhere. When we look at the consumption patterns, what is going up is this: luxury apartments are going up; fancy car sales are going up; malls and restaurants are completely full; hotel rooms are getting pricier.

Sale of mobile phones worth Rs.30,000 is really going well. Price of flight tickets, as my friend is saying, is also going up. These are all the consumption patterns of the rich people which are really, really going up. But those who are actually suffering

are the people in the rural areas. If you look at the consumption patterns in the rural areas, FMGC sales, like sale of shampoos and all those things which give the idea of how they are spending, are actually going down in the rural areas. Sale of affordable homes is going down. Bike sale is going down. Somehow, even after doing all this year and after ? we are increasing the food subsidy, we are increasing MGNREGA allocation and everything ? still we are not able to put enough money in the hands of people so that the rural economy gets revived.

Adding to this is the recent drought condition and also the cyclone that has hit Andhra Pradesh; 103 mandals in Andhra Pradesh have been hit by drought. Cropping in these 103 mandals has come down by almost 40 per cent. Also because of Michaung cyclone, which has hit eight districts of Andhra Pradesh, 20 lakh acres of crop in Andhra Pradesh have been affected. It includes 12 lakh acres of paddy crop, 2.5 lakh acres of chilly crop and 5.5 lakh acres of other crops as well. Even after getting the money and everything from the banks and various places ? farmers are investing so much into that ? they lost to the tune of almost Rs.20,000 per acre. If this is put into the equation of 20 lakh acres being affected, it comes to anywhere between Rs.5500 crore and Rs.6000 crore only in Andhra Pradesh because of the cyclone that has affected them. So, the demand from YSR Congress Party from our State is to increase the number of MGNREGA working days, and to increase the State Disaster Response Fund. We have been given Rs.493 crore which is pittance when we are seeing almost Rs.5500 crore of losses in cyclone itself. So, we want it to be increased to at least Rs.2000 crore.

Also, more importantly, there is a promise made almost two years back in the old Parliament House wherein there was a mention of interlinking of Godavari and Pennar. If it had happened, the drought condition that is prevalent in my district and most of the districts in Andhra Pradesh could have been averted. We have been seeing that and we have been hearing that from the Union Government but the project is not moving anywhere. So, we request and we demand for the people of Andhra Pradesh that this should be fulfilled.

Also, there is a huge outlay of almost Rs.10 lakh crore under capital expenditure in the Budget. We are in the month of December. There are only three months left. Out of that only 57 per cent has been spent until now. Still Rs.4.3 lakh crore have not been spent. Only three months are left. Recently the Railway Minister was there in Andhra Pradesh. He was making a comment. When we asked about the railway zone, he made a comment that the State has not given the land. But I will give you

the other avenues, the other areas where the State has taken the initiative, where the State has given the land, where the State has pursued a number of times. Take, for example, the National Highways. They are not only related to our State; they are related to everyone here. There are a number of projects that have been sanctioned by NHA in Andhra Pradesh. But the seven projects under Bharatmala have been given to Andhra Pradesh wherein more than 90 per cent of the land has been acquired; 3D is done; 3G is done. Amounts have been delivered to the farmers as well. Tenders have been floated. After the tenders have been floated, the first bidder has been identified. After pursuing for four years, after a lot of initiation from our State Government, still the letter of intent has not been given. It is not only related to my State; it is related to most of the States. When we enquired about this why this has been withheld, they kept on saying that there is a new policy that has come into place wherein Bharatmala projects which have not been completed up to 20 per cent have been put on hold. This is the explanation that the Union Government is giving. So, we request that these projects should be expedited.

Also coming to the Polavaram project, this has been the demand of Andhra Pradesh. This has been included as a national project in the AP Reorganisation Act. But we have been asking for it so many times. We know this by heart because we have been repeating it. It is being repeated not only by me, by the Members of my Party as well for the last nine years. Rs.2937 crore of pending bills are there with the Central Government which has not been given. We have been asking for an allocation of Rs.10,485 crore as an *ad hoc* payment so that the project moves. The engineering design and everything is being taken care of by the Central Government. So, they have to look at it.

An allocation of Rs. 10,485 crore, an ad-hoc payment which has been asked by the State Government, has not been done. An allocation of R&R package -- which we have been asking and which will affect the people of Odisha also -- has also not been done.

Now, I come to the educational institutions. There are IITs, IISERs, IIM, NITs, Central University, Petroleum University, Agricultural University, IIIT, Tribal University which have been sanctioned to the State of Andhra Pradesh in the A.P. Reorganisation Act. Nine years have already elapsed but none of these campuses, except AIIMS, are working from a permanent building even now. I am mentioning about all these projects. Land has been given and everything has been given. But

the work is not moving at the pace it is supposed to move. Even we have made a proposal with regard to setting up of new medical colleges. The setting up of 13 medical colleges have been proposed and three have been sanctioned. We are still asking for another ten to be sanctioned, but we are awaiting the response from the Union Government in this regard.

Now, I come to Godavari-Penna rivers interlinking project. We had announced it almost three or four years back. The project is not moving anywhere. They are not able to make Telangana and Andhra Pradesh sit together so as to find an amicable solution. It is not moving anywhere. Almost Rs. 4.3 lakh crore, which has been allocated, has been left behind in capital expenditure which can be spent on this. I request the Union Government to look into this matter.

I am now concluding by mentioning about special category status. This has been the demand of the State of Andhra Pradesh. We have been demanding it for the last nine years. It was promised in the Parliament. We have been requesting for the same numerous times. I know that this is the last year. But we will not stop asking for it. This is a promise made by the Parliament.

Therefore, we request on behalf of the State of Andhra Pradesh, and we demand on behalf of the people of Andhra Pradesh, that a special category status be given to the State of Andhra Pradesh.

Thank you very much.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, सरकार वर्ष 2023-24 की अतिरिक्त 59,378 करोड़ रुपये की मांग ले कर आई है। यह मुख्य रूप से खाद्य, एलपीजी एवं उर्वरक पर सब्सिडी और मनरेगा के लिए माँग की जा रही है। महोदय, आज देश में मंहगाई की समस्या जनता के लिए काफी परेशानी का विषय है। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब तो आरबीआई ने भी अपनी चिंता सरकार को बता दी है। एलपीजी के रेट पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तो साइड ही कर दिया गया है। अच्छा है कि केंद्र सरकार की पार्टी की कई राज्यों में सरकार बन गई है और अब वहां एलपीजी 450 रुपये मिलेगी। फिर हम पूरे देश में एक समान रेट चाहेंगे। बेरोज़गारी की तो कोई बात ही सरकार नहीं कर रही है।

महोदय मैं बिहार से आता हूँ। अतः अपने बिहार राज्य के कुछ बिंदुओं को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। बिहार राज्य विकास की रफ्तार में सबसे पिछले पायदान पर आ गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट और रघुराम राजन कमिटी की रिपोर्ट को देखा जाए। बिहार सरकार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सर्वप्रथम 9 दिसंबर, 2005 को माननीय प्रधान मंत्री जी को मेमोरेंडम दे कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। सरकार एनडीसी के तर्क को आधार मान कर विशेष राज्य का दर्जा देने से इंकार कर रही है। यह रिपोर्ट वर्ष 2012 की है। अब प्रश्न है कि उस समय एनडीसी के मापदण्ड पर 11 राज्यों को

विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। एनडीसी के भी मापदण्ड में पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ापन भी एक मापदण्ड है। वही आधार तो रघुराम राजन और नीति आयोग की रिपोर्ट दर्शाती है और बिहार को देश का अतिपिछड़ा राज्य कहती है। फिर बिहार को हक को क्यों नज़रअंदाज़ किया जा रहा है? बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले 18 वर्षों से बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो भी काम किए हैं। आज सभी राज्य उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी अच्छी योजनाएं कई राज्यों एवं केंद्र सरकार में भी अपने ढंसे से लागू कर रही है। अगर बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, तो यह बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन से उबरने में काफी मदद करेगा और बिहार भी अन्य राज्यों के समकक्ष खड़ा हो जाएगा।

महोदय, अब मैं बिहार के साथ केंद्र सरकार द्वारा कैसे भेदभाव किया जा रहा है, उसका उल्लेख करना चाहता हूं।

पिछले 10 वर्षों में केंद्र के भेदभाव के कारण 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में 14 वें वित्त आयोग और 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा में कमी की गई, उससे अभी तक बिहार राज्य को 61,195.80 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसी प्रकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र- राज्य के अनुपात को भी लगातार घटाया जा रहा है, जिसके कारण वर्ष 2022-23 तक बिहार को 31,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। सर्व शिक्षा अभियान-समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश की राशि 3,799.29 करोड़ रुपये बिहार को प्राप्त हुई, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में घट कर 2,623.90 करोड़ रुपये हो गई। छात्रवृत्ति की राशि राज्य सरकार को खुद वहन करना पड़ रही है, क्योंकि भारत सरकार ने उसमें राशि देना बंद कर दिया है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन में भी लाभुकों की संख्या राज्य में 34,80,775 है। किंतु, केन्द्र सरकार 31,57,256 लाभुकों को ही पेंशन राशि निर्गत करती है और 3,33,495 लाभुकों का लगभग 1358.28 करोड़ रुपये का खर्च बिहार सरकार को वहन करना पड़ता है

बिहार सरकार ने वर्ष 2023 में जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण अपने खर्च पर करवा लिया है। राज्य की अब कुल आबादी 13.07 करोड़ हो गई है। इस गणना ने राज्य में जाति आधारित परिवारों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को सामने ला दिया है। रोजगार की स्थिति भी साफ हो गयी है। सरकारी क्षेत्र में मात्र 1.57 प्रतिशत तथा संगठित निजी क्षेत्र में 1.22 प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध है। बिहार राज्य में कुल आबादी का 24 से 43 प्रतिशत कृषक, मजदूर, मिस्त्री एवं अन्य श्रेणी के परिवार हैं। इनमें 4000 रुपये आमदनी तक वाले 34.13 प्रतिशत हैं, 10,000 रुपये आमदनी तक वाले 29.61 प्रतिशत, 20,000 रुपये तक वाले 18.06 प्रतिशत और 50,000 रुपये से अधिक आय वाले मात्र 9.83 प्रतिशत लोग हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में बिहार को जो राशि मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। राज्य सरकार को प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 में भी उस योजना की मंजूरी नहीं दी गई और मरम्मत के लिए जो योजना आई, उसमें भी एक पैसा नहीं दिया गया।

महोदय, हम लोगों को सौभाग्यशाली कहिए या दुर्भाग्यशाली कहिए, इस विभाग के मंत्री जी भी हमारे राज्य से हैं, लेकिन हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए, वह भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कुछ उल्लेख करना चाहते हैं, जो हमारे इलाके में चलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 106 है, इस विभाग के मंत्री जी तो बहुत डायनेमिक हैं और सभी सांसदों को सुनते हैं, यह गलत नहीं है। लेकिन हमारी जो पीड़ा है, उसे हम बताना चाहते हैं। वीरपुर से उदाकिशुनगंज 106 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका काम वर्ष 2015 में शुरू हुआ और पथ में वीरपुर से सिमराही तक और हरैली से उदाकिशुनगंज तक काम बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। माणिकपुर रेलवे ढाला पर एक आरओबी भी बनना है। कई वर्षों से हम लोग जाते हैं और

देखते हैं कि पिलर बन कर तैयार हो गया है, लेकिन ऊपर का काम नहीं हो रहा है। सिंहेश्वर से माणिकपुर तक एक बाईपास बनना है। इसके सर्वे का टेंडर हो गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी सड़क पर उदाकिशुनगंज-विहपुर कोशी नदी पर पुल सहित 28 किलोमीटर की जो सड़क है, इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी किये थे। इस काम को मार्च, 2024 तक पूरा होना था। हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे कि लोग सभा का चुनाव आएगा, उसके पहले हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन काम की गति इतनी धीमी है कि हमें लगता है कि पुल बनाने में कई वर्ष लगेंगे। उसमें 20 किलोमीटर की जो सड़क है, वह उदाकिशुनगंज से फुलौत तक है। उसमें कलवर्ट बनाकर छोड़ दिया गया है। उसमें पथ निर्माण का काम नहीं हो रहा है। नेशनल हाईवे 107, जो महेशखुंट से सहरसा-पूर्णिया तक जाता है। उसके पैकेज वन में महेशखुंट से सहरसा-मधेपुरा तक 90 किलोमीटर है इसका एजेंसी जीएनएन है। जो एजेंसी होती है, वह अपने आप काम नहीं करती है। वह कागज-पत्र के आधार पर काम तो अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन वह खुद उसे नहीं करती है। उसने पेटी कांटेक्टर राजकेसरी प्राइवेट लिमिटेड, रांची को दे दिया। यह काम वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। इसे दो साल में पूर्ण करना था, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ।

सड़क की स्थिति यह है कि माली, मैना, सोनवर्षा राज में कालीकरण नहीं किया गया। बड़सम, पड़री गांव में भी कालीकरण का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। जो बाईपास है सोनवर्षा-राज, सिमरी-बख्तियारपुर, सहरसा, मठाही में, वहां मुख्य सड़क के बगल में तो थोड़ा काम कर देते हैं, लेकिन समवेदक भीतर तक काम नहीं कर रहा है। दो अंडरपास बैजनाथपुर और सोनवर्षा में बने। दो साल पहले अंडरपास बन गया, लेकिन उसका एप्रोच रोड नहीं बन रहा है। सहरसा में जो आरओबी है, उसका तो काम ही नहीं शुरू किया गया। मठाही, सिमरी-बख्तियारपुर में आरओबी का एक-एक पिलर बनाकर छोड़ दिया गया है। हमने माननीय मंत्री जी से एक सड़क की मांग की थी। बिदूपुर-दलसिंहसराय-सिमरी-बख्तियारपुर-उदाकिशुनगंज-पूर्णिया तक जो 235 किलोमीटर की सड़क है, जब यह सड़क बन जाएगी तो पूर्णिया से पटना आने में 133 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। सोनवर्षा राज से लिटयाही तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

महोदय, एक-दो पॉइंट रेल के बारे में भी कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : सर, कुछ महीने में लोक सभा चुनाव में जाना है। कुछ बोलने नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे यहां सहरसा महत्वपूर्ण स्टेशन है। वह अमृत भारत स्टेशन योजना में सम्मिलित हो गया है, राशि भी दे दी गई है। अखबार में बार-बार रेल के पदाधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। वहां लाइट ओवर ब्रिज गंगजला में स्वीकृत है, उसका भी काम नहीं हो रहा है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : काम भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : रैक पॉइंट शहर में है। धूल से लोग परेशान हैं। स्कूल के बच्चों को भी परेशानी होती है।

माननीय सभापति : मैं दूसरे वक्ता का नाम बोलता हूं, आप समाप्त कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र यादव : इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए।

हम एक अंतिम बात सबके लिए करना चाहते हैं। स्मरण होगा कि तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय जेटली साहब ने भी लोक सभा में इस बात को कहा था। यह बात हम इसलिए कहते हैं कि महंगाई के चलते आम लोग परेशान हैं और सांसद भी उससे अछूता नहीं है। सांसद भी परेशान है। सभी लोग धन-कुबेर नहीं हैं। जिनका कारोबार बहुत लंबा-चौड़ा है, वे बुरा नहीं मानें, लेकिन गरीब लोग भी हैं, साधारण लोग भी हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं। सांसदों के वेतन पर ? (व्यवधान) सरकार को विचार करना चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति : श्री पिनाकी मिश्रा जी।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving my party Biju Janata Dal an opportunity to present our views on this Supplementary Demands for Grants of 2023-24.

Sir, these Supplementary Demands for Grants are about Rs. 45 lakh crore for the year, which was first envisaged in the Budget of 2023-24. It proposes an incremental cash outgo of Rs.58,378 crore, which is an increase of one per cent in expenditure over the Budget Estimates. I compliment the Finance Minister for keeping a very tight fiscal rate in the first Supplementary Demands for Grants, which is very, very possible and doable. I think this House should have no difficulty at all in approving this.

Most of the heads under which the demands are being sought for expansion in expenditure are all related to social sector. One of the heads is chemical and fertilizers which are very important, obviously, for farmers. Then there is defence. There will be nobody in the House who will raise the question on the increase in defence expenditure. Then, there is consumer affairs, food and public distribution. This is particularly a very laudable thing. My Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji was the first person who had requested the hon. Prime Minister I think in December, 2023, that Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana which was to be discontinued starting from 2024, should be continued for another period of at least three to five years.

The Prime Minister acceded to that request and it has now gone up by another five years. Therefore, Rs. 5500 crore for the very marginalised and the poorest sections is absolutely fine and, I think, this House will welcome that.

The additional demand for MGNREGA again is something which, I believed, is very, very important for the rural sector. Although it does highlight one dismal fact that

there has been great poverty still in the rural sector and the rural sector economy, as one of my distinguished colleagues Mr. Srikrishna spoke it, really has not picked up and kept pace the way the urban sector has been picking up in this country. So, there is a lopsided development between this India and Bharat as it is an old conundrum in this country and that continues to obtain. That is a matter of some concern and headache for the Government. I do not know how they are planning to go forward and keep a finer balance in this regard.

There is an additional expenditure being sought for petroleum as well as for providing LPG. Again, this is a welcome move because this gives succour to households which are solely in need of subsidies. As far as telecommunications is concerned, for capital infusion, for optical fibre control-based network services, and for defence services, again, this is very, very laudable.

There is one area where I could not figure out why it has taken such a serious jump from Rs. 18000 crore. It has gone up by Rs. 11000 crores and this is a 61 per cent whopping jump with regards to the Ministry of External Affairs. I believe, it is because of the guarantee of Rs. 9000 odd crores given by the Exim Bank for providing loans but I hope the Minister is able to tell the House why there has been this 61 per cent jump in external affairs which is a little inexplicable.

Coming to the figures put out for the first six months from April to October for tax revenues, one of the issues which will concern the House and which should concern the Government as well is that the GST tax revenues have been collected at only 56 per cent of year's target compared to 63 per cent last year in the same period. I do not understand why this is happening to an economy which is growing at 7.5 per cent and odd. The only obvious reason is that there is clearly a lot of leakage still happening. There is a lot of tax avoidance that continues to happen. I think this is not just in GST because if you look at the income tax numbers, there are only 9 crore tax assesses in a population of 140 crore and out of them, the actual tax payers, three crores and odd file nil returns. All tax assesses are not tax payers. So, only 6.65 crores actually pay some tax. Out of that, 76 per cent comes from only 32 lakh people which is five per cent of the tax payers. Therefore, the tax base is clearly still exceptionally narrow compared to this vast population that we have here. The hope of the Government of cash shrinkage in the economy clearly has not worked out as Rs. 32 lakh crore today is the cash in circulation. Many of us are witnessing the kind of cash that has been pulled out of the cupboards. If 32 lakh crore is double of what it was in 2016, when demonetisation took place when

it was 16 lakh crores, it is a double of that amount today in circulation. Therefore, the tax collection system and the tax laws clearly in this country are not sufficing. I know that my colleague Mr. Nishakant Dubey had earlier lamented that people in the House are speaking on everything except the Demands for Grants, I have tried to keep to the Demands for Grants but this has been the convention of the House cutting across party lines that people do it during Supplementary Demands for Grants and speak on other issues relating to their State as well. So, there is a breach of that so called rule and, therefore, I will stick to the breach and mention five problems of my State before you, Mr. Chairman, and through you to the Minister.

First is the release of State-specific grants as per the recommendations of the Fifteenth Finance Commission. The Fifteenth Finance Commission had recommended Rs. 775 crores for Odisha during 2022-23 to 2025-26. This includes Rs. 800 crore towards early-warning dissemination system for cyclone-prone areas. Everybody in this House knows how every year Odisha is virtually prone to massive cyclones on the Eastern coast. Therefore, this is absolutely of paramount importance and we would request the Union Government, through you, to expedite release of the State-specific grants including those which relate to the specific needs of the State, as identified by the 15th Finance Commission.

The second point relates to the Centrally-sponsored schemes. There should be an advance indication. This is not just Odisha but I think every State has the same lament here. We as Members of Parliament represent our different States and all the States have the same concern that there should be an advance indication about the annual allocation for each State at the time of Budget formulation so that the States will be able to prepare the Budget on a more realistic basis. What is happening today is a complete *ad hoc* functioning through the year as a result of which the release of funds does not match the allocation. We in Odisha have experienced such irregular flow of funds in many of the schemes that the actual Central assistance eventually turns out to be substantially lower than what was either approved or anticipated in the beginning of the year. Therefore, Sir, we urge the hon. Minister, through you, that the Government of India should evolve a single window system for communication of annual allocation and sharing pattern of all Centrally sponsored schemes to the States and ensure release of Central assistance, as per commitment, at the earliest.

Point number three is again specific to Odisha. We have had a huge trouble because of the delinking of eight Centrally sponsored schemes from Central support. Discontinuance of special plan for KBK districts ? Koraput, Balangir, Kalahandi, which are the most backward districts in the country, and discontinuance of Central assistance for IAP districts, and abolition of normal Central assistance and steep increase in the State's share of Centrally sponsored schemes have imposed a severe financial burden on the State. So, with natural disasters, perpetually besetting Odisha, our request to the Central Government is this. Now that you have done away with this whole thing of providing special category status to States, kindly at least work on what Mr. Naveen Patnaik has repeatedly requested the Centre. We are requesting you to accord Odisha and also three or four other States, 'special focus status' so that at least, there is some immediate succour to us.

Point number four relates to the restoration of Central assistance for area development programmes in Left Wing States. These include not just Odisha but also our neighbouring States like Telangana, Andhra Pradesh and Chhattisgarh, which have the same problem. So, this discontinuance of Central assistance for area development programmes of KBK backward region, IAP and LWE States, has affected the development programmes of all these States. So, I speak on behalf of all these States when I request the Central Government for restoration of central assistance for these area development programmes.

Lastly, Mr. Chairman Sir, as the entire House knows, Odisha is a pioneer in power sector reforms since 2000 when Mr. Naveen Patnaik first took over the charge of Chief Minister almost 24 years ago. He has had his five terms now, and going into sixth term. After August 2024, he will be the longest serving Chief Minister in this country, and I dare say, that is a record which is unlikely to be broken for a large State or a medium sized State like Odisha. Mr. Pawan Chamling from Sikkim is the only person now who is the longest serving Chief Minister, and Mr. Patnaik will cross that record in August 2024. May God bless him with a long life.

Odisha is a pioneer in power sector reforms and we have adopted the PPP model in all the areas of distribution, etc. But while the State has been a beneficiary of some rural electrification schemes, we have been kept out of the IPDS and the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana. Therefore, the DISCOMS in Odisha are being deprived of the Revamped Distribution Sector Scheme which is not helpful at all for the consumers because prices continue to remain inordinately high.

Therefore, in order to provide electricity at lower tariffs to the consumers at large, I would request the hon. Minister, through you, to kindly look into this aspect.

Mr. Chairman, I am also very grateful to you for having given me the time to present my views on the First Batch of Supplementary Demands for Grants. Thank you very much.

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, I would like to talk about the State of Telangana as there are a number of long-pending demands which remain unfulfilled in spite of regular follow-up and correspondence by our BRS Party President KCR Sir, State Ministers and MPs to the Central Government.

The major demands include fulfilment of promises made to Telangana in the AP Reorganisation Act, 2014, industrial incentives, national project status for either Kaleshwaram or Palamuru-Rangareddy Lift Irrigation Scheme and increase in seats in the Legislative Assembly from 119 to 153 by way of delimitation.

The BRS Government has been demanding setting up of a railway coach factory in Kazipet but instead of that, a Periodical Overhauling Workshop was sanctioned after a decade, and the coach factory moved to Gujarat.

Moving further, the Bayyaram Steel Plant in Mahabubabad, Navodaya and Sainik schools in every district, and clearing Rs.900 crore arrears pertaining to the Central grants for the development of backward regions still remain on the cards.

Our Government also demanded that the Centre abolish the GST on handlooms, pay Rs.7,778 crore towards the Central Government's share for urban infrastructure projects being undertaken by the Municipal Administration Department, increase reservation for SC, ST and BC in proportion to their ratio of population, and reduction of petrol, diesel and LPG prices.

We have been demanding lifting of restrictions on the MGNREGA programme, linking MGNREGA with agriculture, providing Mission Bhagiratha with a Central grant of Rs.19,205 crore, Mission Kakatiya with a grant of Rs.5,000 crore, and providing various irrigation projects with a grant of Rs.817 crore as recommended by the NITI Aayog as well as Central grants recommended by the Fifteenth Finance Commission such as Rs.723 crore special grant, Rs.6,268 crore under the State-specific and Centre-specific grants.

Our Party has also sought a Bulk Drugs Park in Hyderabad. We also requested for sanction of a Software Technology Park of India (STPI), Rs.800 crore towards Centre's share for development of roads and corridors, link roads in Hyderabad and city outskirts, and Rs.450 crore for the Mass Rapid Transit System in KPHB-Kokapet-Narsingi corridor.

Sir, extreme unfairness has also been meted out to Telangana State in the budget allocation in regard to major railway projects. Despite repeated appeals from the State Government, the Union Government did not grant any new major infrastructure project to improve the rail connectivity in the State.

Telangana contributes substantially to the revenue of South Central Railway, both by way of freight and passenger transport. The State is a crucial link between North and South India, and is home to the most important railway junctions, Secunderabad and Kazipet, in our country.

Being a landlocked State, Telangana is heavily dependent on the railway infrastructure for transportation of goods and passengers. Addition of new railway infrastructure will be a big boost to the State's growth. But the Union Government is found wanting when it comes to extending necessary assistance to develop new transport infrastructure in Telangana.

This clearly shows the lack of interest of the Union Government in developing railway infrastructure in Telangana. Many other projects for which survey reports have been submitted long back have also not moved an inch.

Funds should be allocated for NIMZ in Zaheerabad. The industrial corridor to be developed between Hyderabad-Warangal and Hyderabad-Nagpur also needs the support of the Centre.

It has been estimated that the roads that connect Hyderabad Pharma City with NIMZ in Zaheerabad need Rs.5,000 crore funding.

The Hyderabad-Vijayawada Industrial Corridor is estimated to cost Rs.5,000 crore.

Then, these are my other demands. Along with the above mentioned projects, we expect from the Centre for gas allocation for the Common Effluent Treatment Plant for the industrial park in Jadcherla under TIES.

We need clearance for the setting up of brownfield manufacturing clusters and upgradation.

Reopening of the Cement Corporation of India's unit in Adilabad is required. The National Design Centre should be located in Hyderabad. We require allocation of funds for the Hyderabad Pharma City. Hyderabad should be included in the Defence Industrial Production Corridor which the Centre is going to create.

We need support for the Mega Textile Park in Warangal. The project needs at least Rs.500 crore in the form of seed capital. We request sanction of a mega powerloom cluster for Sircilla, encompassing textile, weaving, and apparel parks under the Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme. We need upgradation of powerlooms under the IN-SITU scheme. We need sanction of block level handloom clusters under the National Handloom Development Programme (NHDP).

16.00 hrs

Some other expectations that people of Telangana have with the Government of India are like setting up of the Indian Institute of Handloom Technology, setting up of the campus of National Aviation University in Hyderabad, reconsidering the creation of ITIR or the sanction of a project of the same size, setting up of an Integrated Steel Plant in Khammam as part of the promise made in the Andhra Pradesh State Reorganisation Act of 2014, and special incentives for industries in Telangana.

I, therefore request the hon. Minister to kindly take a note of the said projects and sanction funds for the same. With these words, I conclude and support the Bill. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to speak on the Demands for Grants on behalf of the Nationalist Congress Party. I am a little confused by the contradiction in this Government.

Sir, Mr. Gaurav Gogoi and Prof. Sougata Rai extensively spoke about the growth story of this country, and they also spoke about GST and several other issues. But I think the most alarming issue that this country right now faces is unemployment. At one level the Government says that the country is doing extraordinarily well. So, could the hon. Finance Minister explain to us, I wish Nirmala ji was here today to explain to people like us who are not financial experts, if the economy is doing so wonderfully well, why is there so much unemployment in this country? This is not

my data, this is your Government's data, which is very, very concerning for all Indians who are aspiring and looking for a good life on merit.

Besides this, you look at the information technology. In Maharashtra, where I come from, there is a Rajiv Gandhi Information Technology Park in Hinjawadi. This is one of the finest examples of technology and IT industry created in Maharashtra which we are very proud of. This is in my constituency. महाराष्ट्र के लोगों द्वारा उसको मेहनत से बनाया गया है। आज वह पूरा आईटी सेक्टर प्रैशर में है। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसके बारे में सरकार क्या करेगी और पॉलिसी लेवल पर आप क्या इंटरवेंशन करेंगे, इसके बारे में आप बाद में समझा दीजिएगा।

16.02 hrs (Shri Shrirang Appa Barne *in the Chair*)

Sir, the reason why I said this Government is about contradictions and highly confused is because of the three main policies. One is, kisan produce, दूसरा इथेनॉल और तीसरा पॉवर। आप पूछेंगे कि किसान कैसे, गौरव गोगोई जी ने उसके बारे में बोला है, लेकिन मैं आगे सरकार से पूछना चाहूंगी कि आप किसानों के बारे में कह रहे हैं कि उनको जो पैसा मिलता है, हम उसको दोगुना करेंगे। मैं प्याज के बारे में आपकी कल की पॉलिसी बताना चाहती हूँ। आप तो महाराष्ट्र के हैं। मेरा और उनका निर्वाचन क्षेत्र अगल-बगल है। आप उनसे उनका दुःख पूछिए। आपकी जो मंत्री हैं, शायद भारती ताई यहां नहीं हैं, उनके घर पर भी काफी लोग कल मिलने गए थे। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्याज का किसान है। प्याज कौन उगाता है? कराड सर, आप तो मराठवाड़ा से आते हैं, वह कोई जागीर नहीं होती है, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है। प्याज वाला किसान कम पानी में, जिसके पास कम लैंड होती है, वही किसान प्याज की खेती करता है। उसके ऊपर आपने टैक्स लगाया है और वह भी 40 टके टैक्स लगाया है। अभी आपने एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया है। उसका प्राइस पूरा क्रैश हो गया है। प्याज का किसान, जो छोटा किसान है, क्या आप उस पर यह अन्याय करेंगे? महाराष्ट्र में सारे किसान, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, एमओएस, फाइनेंस भी महाराष्ट्र से हैं, आप सबको पता है कि आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। The same thing is with rice. बाकी राज्यों में वही हाल है। आज सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। मेरी इस सरकार से विनती है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम उनकी आमदनी दोगुनी करेंगे और दूसरी तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं। आप एक्सपोर्ट भी बैन कर रहे हैं। They are consistently inconsistent. This is the quality of this Government when it comes to the farmers' policies.

मैंने पांच नहीं छः महीने पहले पीयूष गोयल जी को एक ट्वीट किया था कि जो प्याज का किसान है, आप उसको नहीं देख रहे हैं, आपको वे नहीं दिख रहे हैं। बाद में, उनकी पूरी आर्मी ने ट्रोल भी किया कि इनको क्या पता है। किसान देख रहे हैं कि मैंने जो छः महीने पहले कहा था, वही आज यह सरकार कर रही है। आप देखिए कि आज प्याज का किसान क्या कर रहा है? आप उसका एक्सपोर्ट क्यों बैन कर रहे हैं? देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी 40 टके टैक्स नहीं भरता है, लेकिन मेरे यहां जो सबसे छोटा किसान है, उसके ऊपर इन्होंने 40 टके टैक्स लगाया है?

महोदय, ये कौन-सा न्याय है? ये एक किसान का उदाहरण है। दूध का अलग है। दूसरा, मैं किसान के बारे में बताऊं कि इथेनॉल की पॉलिसी क्या है? मैं हंसू या रोऊं, इस सरकार ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। श्री पीयूष

गोयल जी इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं। गुरुवार को यहां खड़े होकर हमें बड़ा लेक्चर दिया था कि कैसे वर्ष 2014 के बाद इथेनॉल का क्या किया। इन्हें तो वर्ष 2014 से पहले का एमनेशिया था, इसलिए इनको पता नहीं है। आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, तो आप जानते हैं। शायद कॉमर्स मिनिस्टर नहीं जानते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्रीज़ 50 सालों से इथेनॉल बना रही है।?(व्यवधान) वे शायद मुंबई के हैं, शायद पता नहीं होगा। हो सकता है, पता भी हो, लेकिन भूल गए होंगे।

उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी के बारे में बात की थी। वे गुरुवार की सुबह यहां पर बोल रहे थे कि इथेनॉल में ऐसा करेंगे, एक्सपोर्ट अलाई करेंगे, ये करेंगे, फलाना-ढिकाना, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। मैं भी हंस रही थी। वे वर्ष 2014 का इतिहास बता रहे थे। उसके पहले का उनको नहीं पता था। गुरुवार की सुबह इथेनॉल पॉलिसी के बारे में इतना अच्छा-अच्छा बोले, सभी किसान खुश हो गए कि कॉमर्स मिनिस्ट्री इथेनॉल के लिए बहुत कुछ कर रही है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे क्या न्यूज़ आई कि ethanol production from sugar will be banned. Is it not a contradiction? 24 घंटे में एक ही मंत्री दो निर्णय लेते हैं। एक दिन ये बोलेंगे, दूसरे दिन वो बोलेंगे। आप गुरुवार को बोलते हैं कि इथेनॉल को प्रमोट करेंगे और शुक्रवार यानी 22 घंटे के अंदर पॉलिसी बदल गई। आज सारी शुगर फैक्ट्रीज़ रो रही हैं। कल मैं उनसे मिली थी। उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, बड़े मंत्रियों के फोन्स आए थे, सबके फोन्स आए थे।?(व्यवधान)

Sir, I am not yielding. I never distract anybody. ? (*Interruptions*) मैं आपको इथेनॉल, दूध, प्याज के बारे में बताऊं। शुगर फैक्ट्री में यू-टर्न लिया, दूध में भी यही हाल है। इनकी सरकार प्राइसिंग में गड़बड़ी करती है। मुझे अभी भी याद है कि सुषमा जी हमेशा कहती थीं। आप पुराने हैं, आपको भी याद होगा। वह बिचौलियों के बारे में बात करती थीं। वह हमेशा कहती थीं कि न तो किसान को पैसा मिल रहा है और न ही ग्राहकों को कम दाम पर सामान मिल रहा है। बीच का हिस्सा बिचौलिया खा रहा है, तो उस बिचौलिए का क्या हुआ? आज महाराष्ट्र में किसान को दूध का 25-26 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है और शहरों में डबल प्राइस पर है, तो बीच का पैसा कौन-सी सरकार लेकर जा रही है? इस सरकार में बिचौलिया कौन है? यह तो बताइए। दूध की पॉलिसी में कंप्यूजन, इथेनॉल में यू-टर्न और प्याज में यू-टर्न, मैं ऐसे कितने उदाहरण बताऊं। ये सरकार सभी किसानों के खिलाफ है। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं पॉलिसी पर सवाल पूछ रही हूं।

उसके बाद पावर का भी वही हाल है। मैंने आपको पावर के बारे में बताया था कि ये क्या करते हैं। मैंने फूड के बारे में बोला, इथेनॉल के बारे में बोला, अब मैं पावर के बारे में बताती हूं। इन्होंने कहा कि इनकी सरकार ने थर्मल का नया कमिटमेंट किया है। आप 80,000 मेगावाट थर्मल पावर 2032 में जेनरेट करेंगे। इनकी सरकार हर समय एन्वॉयरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बोलती रहती है। Is it not a contradiction? थर्मल पावर करेंगे और कोप की एक मीटिंग में जाकर बोलते हैं कि हम लोग रिन्यूएबल में करेंगे। What is the policy of this Government on power? Are they going to do renewables or thermals? Which one is true? पूरी दुनिया में जाकर कुछ और कहते हैं और पॉलिसी लेवल पर यहां कुछ और कर देते हैं। It is a highly confused Government of contradictions! एक ही मंत्री कुछ और कहता है। Is the Environment Ministry not talking to the Power Minister? मैं पिछले हफ्ते ही जम्मू-कश्मीर के बारे में बोली थी। श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं मिलती है, तो गांवों में क्या होता होगा? This is only one example.

महोदय, आप जहां से आते हैं, मैं भी उसी राज्य से आती हूं। आपको पता है कि हमारे किसान हमें कितनी बार बोलते हैं कि हमें 8 घंटे में नहीं, बल्कि 6 घंटे में बिजली चाहिए। एक जगह ये नेशनल ग्रिड बनाकर कह रहे हैं that national grid is doing well. Where has this gone? I want to ask this Government of contradictions. This Government is a highly confused Government. पावर में फेल्योर, इथेनॉल में फेल्योर, किसानों के बारे में फेल्योर और मैं इनके कितने फेल्योर गिनाऊं? You have to ask them and they have to answer.

ये क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करेंगे? क्लाइमेट चेंज पर बड़े-बड़े भाषण देते हैं। हमारे महाराष्ट्र में आपके और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं, वे कितनी प्रदूषित हो गई हैं। हमारे यहां खड़कवासला है, जो इनकी नई पॉलिसी आई है, उसके कारण सभी लोग घर बना रहे हैं। आप वहां आ चुके हैं। खड़कवासला का सब गंदा पानी नाले में जाएगा, वही नदी में जाएगा, वही आपके खेतों में आ जाएगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र और आपके निर्वाचन क्षेत्र में चला जाएगा। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? There is no policy or standardisation of policy, be it climate change, be it power, be it *kisan*. ये इन्फ्रास्ट्रक्चर की इतनी जोर-जोर से बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इनको तो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बाकी सोशल सेक्टर्स बंद हैं, सिर्फ बिग टिकट इन्फ्रास्ट्रक्चर चल रहा है।

सर, आपको तो पता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन ये बिग टिकट वाले नहीं चाहिए। इसके कारण वह आपको भी मिले हैं। मैं उससे पहले एक छोटा पॉइंट बताऊंगी। सर, ने एक जवाब दिया था कि Indian banks write off Rs. 10.6 lakh crore in five years, out of which 50 per cent are linked to large corporates. I know what you will say. Your answer also says that it is not a write off. We are just making sure that it is recovered and that apart from time, value loss, inordinate delays result in asset value deterioration which hampers ultimate growth, ultimate recoveries. This is your reply. You are saying you are not writing off Indian banks but you are either reorganising, selling their assets. Is it not another contradiction? You are only cleaning your budget books. You are saying it is not a write off. This is your statement, not mine. So, how does this help the economy?? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुप्रिया जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: अगर यह भी करना हो तो आप इनके लिए भी कर सकते हैं। आप हमारे किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते हैं? महाराष्ट्र में आपकी पॉलिसी गलत है। वहां कहीं सूखा है, कहीं ओले पड़े हैं। आप हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दीजिए। मैं किसानों की तरफ से मांग करती हूं। जैसे आप इनका राइट-ऑफ कर रहे हैं, वैसे ही आप किसानों का भी कर्जा माफ कर दीजिए। ? (व्यवधान) This is all juggling of the books, nothing else. उसके बाद सीनियर सिटीजन की बात है, जो मैंने सुबह भी बोली थी। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है और मैं बोल रही हूं कि यह बिग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। आप छोटे लोगों को भी याद रखिए, जिनके कारण हम सब हैं।

Your Government has introduced EPS-95 and NPS. Prakash Javadekar ji was your spokesperson who talked about it. चेरर को पता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भीमा साखर शुगर फैक्ट्री

है। अभी उदासी जी बोल रहे थे, उनके राज्य के एक एमएलए ने यह फैक्ट्री ली है। यह भीमा साखर कारखाना दौंड, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यह पहले बीजेपी के एमएलए की फैक्ट्री थी। उनकी फैक्ट्री के सारंग सोपान कांबले जी हैं, जिन्होंने 33 साल फैक्ट्री में काम किया। Each month contribution of EPF was Rs. 500. सारंग सोपान कांबले, जो भीमा साखर शुगर फैक्ट्री, पाटस, तालुका दौंड, डिस्ट्रिक्ट पुणे में थे, वह 500 रुपये हर महीने देते थे। अभी उनको हजार रुपये भी नहीं मिलते हैं। आप यह सोचिए कि दोनों सीनियर सिटीजन पति-पत्नी साथ में रह रहे हों और उनको हजार रुपये मिल रहे हों तो क्या बहू उनको मान-सम्मान देगी? अगर उसको अपने नाती को एक छोटा सा गिफ्ट देना हो तो वह कहां से देंगे?

सर, ईपीएस-95 और ओपीएस का कमिटमेंट आपकी सरकार ने किया था कि जब हम सरकार में आएं, हम करेंगे। यह पैसा कहां जाता है? यह आप ही के पास सरकार में आता है? हेमा जी तो प्राइम मिनिस्टर जी के पास गई थीं, फिर आगे क्या हुआ? Where is this money? It is their hard-earned money. एक विश्वास के साथ वह आपकी सरकार को दिया था। ईपीएस-95 और ओपीएस के पैसे का क्या हुआ? ये पेंशन के पैसे हैं, सरकार के पैसे नहीं हैं। इसके बाद एक और बड़ा इश्यू है, जो पेंडिंग है, वह आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ीज़ का है। आप सोशल सेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। You only want to build bridges, big infrastructure projects. But what about ASHA workers and Anganwadi sevikas? वह पैसा भी नहीं आ रहा है। वयोश्री योजना दिव्यांग में मेरा निर्वाचन क्षेत्र सबसे हाई परफॉर्मिंग रहा है। हमारा पैसा नहीं आ रहा है। You do not have money for social justice.

I will make one last small point about the relationship between States and Centre. आपने तो बहुत बेस बढ़ा दिया है। राज्यों को लोन चाहिए है तो ले लीजिए। So, States are also taking it, क्योंकि सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स के लिए पैसा मिलता है। But the gap is becoming so bigger. इंटरैस्ट में ही राज्य दबे जा रहे हैं। ऐसा न हो कि जीडीपी और आपने जो डैट लिया है, उसके इंटरैस्ट में राज्य दब जाएं। अगर राज्य दब गए तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? What will happen? You are so proud people are spending. From a savings economy, we have become a spending economy. Culture has changed. लोग मोबाइल से भी ईएमआई भर रहे हैं। You are saying that all these robust activities are taking place. Even my friend also talked about it earlier. Mr. Krishna said it. Several MPs have said that there is this gap between the economies. Rural economy is not doing as well as the urban economy like you think it is doing. I am not criticising your Government. हर सरकार कुछ तो अच्छा कर ही लेती है। ऐसे नहीं होता है। So, in all your good projects, I urge you to relook at all this. In the last five years, be it IMF or any other rating, it goes up and down.

There is no consistency. Mr. Dubey may say anything about COVID-19 times, but we have taken our time. A lot of States have bitten the bitter bullet to come into this game. So, let us not give all credit to the Central Government. I urge you to relook at your numbers and not only look at infrastructure projects, but even look at the bottom of the pyramid be it pensioners, women, etc. who really need help. Thank you very much.

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फोर ग्रांट्स में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। रूरल डेवलपमेंट में 14524 करोड़ रुपये मांगे गए हैं, I believe that this should have been more than Rs. 1 lakh crore because जो मजदूरों को तीन सौ रुपये के आस-पास दिया जा रहा है, वह बहुत ही कम है। अगर स्टेट्स में देखेंगे तो 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन मिलता है। मेरी गुजारिश होगी कि इस 300 को 500 किया जाए और 100 दिन के रोजगार को 150 दिन किया जाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी की सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी है। अमीर-अमीर हो रहे हैं और गरीबों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि लगभग 5.68 करोड़ हाउसहोल्ड इससे लाभान्वित होते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि 39 परसेंट हाउसहोल्ड को इस साल में काम नहीं मिला है। मेरी गुजारिश होगी कि इसको सीरियसली लेना चाहिए और खासकर के इसका इम्पैक्ट बिहार पर पड़ता है, जिसकी आबादी 14 करोड़ के आसपास है और जैसा कि हमारे बीजेपी के साथी ने बताया कि 4 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं। ज्यादातर इनह्यूमन कंडिशन, हार्डशिप में काम करते हैं, ताकि वे अपने परिवार को पाल सकें। इस सरकार से मेरी गुजारिश होगी कि बिहार की स्थिति को देखते हुए बिहार का पर-कैपिटा इंकम पूरे देश में लोएस्ट है, वन थर्ड है बाकी स्टेट के मुकाबले। इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा देना चाहिए और साथ ही साथ अगले पांच सालों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की सहायता मिलनी चाहिए, जिसमें से एक लाख करोड़ रुपये सीमांचल को देने चाहिए क्योंकि वर्ष 2021 के नीति आयोग की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सीमांचल का एरिया हिन्दुस्तान का सबसे गरीब इलाका है और गरीब ही नहीं, उसमें से हर तीन आदमी में से दो आदमी बिलो पावर्टी लाइन में है। इसलिए अगर सही मायने में सबका विकास सबका न्याय वगैरह, वगैरह, जो आदरणीय मोदी जी कहते हैं, अगर सही में वह मायने रखता है तो उस पर विचार करना चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में उन्होंने बिहार के लोगों की बोली लगायी थी और सवा लाख करोड़ देने की बात की थी। मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहूंगा कि उसमें से कितना दिया गया? मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिया गया और यही नहीं हमारे एक बिहार के सीनियर नेता ने बताया कि एजुकेशन में, सर्व शिक्षा अभियान में 46000 करोड़ में से सिर्फ 16000 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं, जिनमें कम दिया गया है। इसको बंद करना होगा। तीसरा, अगर सही मायने में इलाके को इम्पूव करना है तो मेरे पार्लियामेंटरी एरिया में 12 ब्लॉक्स हैं। मैं चाहता हूँ कि हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल, नर्सिंग, लॉ, बिजनेस, आर्टिटेक्चर वगैरह के कॉलेजेस बनने चाहिए। मेरे यहां एजुकेशन की बैकवर्डनेस को देखते हुए, यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने यह फैसला किया कि वहां के लोगों को एजुकेशन का मौका देना चाहिए। वहां 136 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए और उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पिछले दस साल से हमें न्याय नहीं मिला है और पिछले साढ़े चार साल से मैं यहां डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहां तक कि एएमयू से भी आवेदन आया है कि Rs. 352.75 crore should be given to them apart from Rs. 126.82 crore. I would like the hon. Minister to kindly facilitate it. The UGC has sanctioned 29 teaching and 19 non-teaching staff और साथ ही साथ यूजीसी सैंक्शंड 29 टीचिंग और 19 नॉन टीचिंग स्टाफ मिलना चाहिए।

इसके साथ ही साथ किशनगंज में और बायसी में सैनिक स्कूल होना चाहिए। सरकार के द्वारा हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कही गई थी। हमारे यहां पर एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वहां पर एम्स दिया जाए, ताकि बंगाल और ओडिशा के लोगों को भी फायदा पहुंचे।

सर, खासकर माइनोरिटीज का जो इश्यू है तो स्कॉलरशिप को रिस्टोर करने की जरूरत है। आपको ताज्जुब होगा कि मुसलमानों की 14 परसेंट की आबादी है, only 4.4 per cent of Muslim population enrol into higher studies. It is a ? on this Government कि इस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि एनरोलमेंट को इंप्रूव किया जाए। अक्सर हमने देखा है कि डिमोलिशन ऑफ मॉस्क मजार हो रहा है। इसको बंद करने की जरूरत है। Remove encroachments from Waqf properties from all over India. Take strict action against communal hate speeches delivered by leaders of the Ruling Party. मीडिया पोस्ट्स पर भी निगरानी रखनी चाहिए। जो लोग हेट को प्रमोट करते हैं, वे हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

मैं हमारे यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पीएमकेवीवाई के तहत हमारे यहां पर जूट, बैम्बू, वाटर हाइसिंथ वगैरह कई चीजें हैं। उनके लिए ट्रेनिंग दी जाए। हमारे यहां पर ?खेता? एक आर्ट है, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। उसको जियो टैग मिलना चाहिए और उसका हर ब्लॉक में ट्रेनिंग सेन्टर होना चाहिए तथा हर पंचायत में बैम्बू, जूट वगैरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है। सरकार ने दो करोड़ जॉब प्रति साल देने का वायदा किया था, लेकिन क्या मिला? भैया, आप बताइएगा कि क्या मिला है? मैं चाहता हूँ कि कम से कम ट्रेनिंग तो मिले, जिससे हम लोग अपना एम्प्लॉयमेंट सेल्फ जनरेट कर सकें। सर, पीएमजीएसवाई की हालत खराब है। दो साल से हमें फंड नहीं मिला है। हमारे यहां पर कोई रोड और पुल नहीं बना है।

मैं कुछ पुल्स का नाम बताना चाहता हूँ। मथुरापुर, छिलमाडी, खरखरी, निचितपुर, मिर्जापुर, लोधाबाड़ी, सोलघाट, गोरुमारा, रियाद अली, सिमलबाड़ी, अशियानी, दुब्बा धार और सड़कों में डंगराह, बागडोव वगैरह-वगैरह ये बहुत महत्वपूर्ण पुल्स और सड़कें हैं और इनका काम पूरा करने की जरूरत है। रेलवे में किशनगंज से जलालपुर रोड के लिए हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो और इस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।

कोविड के दौरान कई ट्रेन्स का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था और वह अभी भी बंद है। मैं चाहूंगा कि उन्हें वापस शुरू किया जाए और किशनगंज और गलगलिया स्टेशन पर रैंप पॉइंट हो तथा बाकी स्टेशन्स, पुठिया तथा तैयबपुर को डेवलप किया जाए।

सर, हमारे यहां पर महानंदा बेसिन का प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन उसका काम नहीं किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अगले तीन-चार सालों में इसे कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी हजारों एकड़ प्रोडक्टिव जमीन बर्बाद हो जाती है तथा कई गांव कट जाते हैं इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसलिए जाम लग जाता है, चूँकि पॉपुलेशन ज्यादा है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो मैं प्रपोज करना चाहूंगा कि केलटैक्स चौक, रुईधासा मैदान के पास किशनगंज में, बेलवा में, डगरुआ में, बायसी में, अमौर में तथा रौटा में फ्लाईओवर बनाया जाए।

सर, अगर हिन्दुस्तान को वाकई विश्वगुरु बनाना है और डेवलपड नेशन बनाना है तो आपको सबको एक साथ लेकर चलना होगा। आप चाहेंगे कि बिहार के आठ करोड़ लोग बाकी राज्यों में जाकर उन राज्यों का जीडीपी बढ़ाए और पर कैपिटा तीन गुना बढ़ाए और हम लोग वन थर्ड पर रहे तो हिन्दुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको सबको लेकर चलना होगा। यह मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। मैं खासकर के किशनगंज और सीमांचल एरिया की बात करूंगा। It is also geographically very important. एक

तरफ नेपाल है और बगल में बांग्लादेश है। दोनों कंट्रीज जो हमारे से बहुत पीछे थी, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बढ़ गई है और हमारी दिन ब दिन घटती जा रही है। मेरी गुजारिश होगी कि मैंने जो स्पेशल स्टेटस और पांच लाख करोड़ रुपये की बिहार के लिए मांग की थी, वह सरकार कबूल करे और अगले पांच सालों में बिहार का पांच लाख करोड़ रुपये का पैकेज हो, जिसमें से कम से कम एक लाख करोड़ रुपये का सीमांचल पर खर्चा हो। बाकी स्टेट्स की तुलना में हमें जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, वह हमें मिले।

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लिमेंट्री डिमांड्स फोर ग्रांट्स पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर पार्टी ने दिया है। हम सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज विश्व भर में संकट का माहौल है। वर्ष 2022 से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और आज के समय में यूक्रेन का युद्ध एक स्टैंडस्टिल पर आ गया है, न जाने इसका क्या परिणाम विश्व और विश्व की अर्थव्यवस्था पर होगा? इसके साथ-साथ अभी जो हमारा प्रहार हुआ, उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में संकट आ गया है। वहां युद्ध चल रहा है। इसका क्या परिणाम होगा, यह कहना मुश्किल है। अभी सुप्रिया जी ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा है। उसके जो हानिकारक प्रभाव है, हमें भी अब वे विश्व में नजर आ रहे हैं। विश्व में बहुत जगहों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो रहा है। आज पूरे विश्व में एक संकट का माहौल है, लेकिन इस संकट के माहौल में अगर एक देश की अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि आज के समय में बिल्कुल दुरुस्त है, वह चमकता हुआ सितारा है, तो वह भारत की अर्थव्यवस्था है। यह इसलिए है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा, अपने सकारात्मक नीतियों के द्वारा इस संकट के माहौल में भी हमारी अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता दी है और एक दिशा दी है। मैं उसके लिए मानता हूं कि पूरा देश और हम सभी माननीय सदस्य उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज के समय में हम लोगों की यह स्थिति है।

अगर हम बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि सुप्रिया जी ने कहा है कि अभी देश में बेरोजगारी की स्थिति है, तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी सिर्फ ऐसे राज्यों में है, जैसे हमारे झारखंड में है। झारखंड में इसलिए दयनीय स्थिति है, क्योंकि अगर वहां कोई भी उद्योग चल रहा है, तो वह सिर्फ भ्रष्टाचार का उद्योग चल रहा है, ट्रांसफर-पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये, जो कैश निकल कर आया है, वह यह दर्शा रहा है कि इस राज्य में क्या परिस्थितियां हैं? इस राज्य में हमारे जो प्रतिभावान युवा हैं, हमारे जो मेहनती युवा मित्र हैं, उनको कोई चारा नहीं है। उन बेचारों को लाचार होकर पलायन करना पड़ता है। गनीमत है कि ऐसे राज्य हैं, जहां हम लोगों की सरकार है, जैसे महाराष्ट्र, जहां से सुप्रिया जी चुन कर यहां आई हैं, वहां अभी भी रोजगार का सृजन हो रहा है। जहां-जहां रोजगार का सृजन हो रहा है, हमारे लोग वहां पलायन करके काम कर रहे हैं। यह आंकड़े बता रहे हैं। आप ईपीएफओ का डेटा देखिए, अनइम्प्लॉयमेंट का डेटा देखिए, जो रिकवरी आई है, आज हमारी जीडीपी ग्रोथ सात प्रतिशत हो चुकता है, हमारा निवेश बढ़ता चला जा रहा है। उसके द्वारा स्पष्ट नजर आ रहा है। जहां-जहां अच्छे राज्य हैं, जिनकी अच्छी नीतियां हैं, जिनकी दूरदर्शी, प्रभावशाली और सकारात्मक नीतियां हैं, वहां रोजगार का सृजन हो रहा है एवं वहां लोगों को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है।

उदाहरण के तौर पर, मैं आपको अपने हजारीबाग, पतरातू के बारे में बताना चाहता हूं। मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सुप्रिया जी को समझाना चाहूंगा कि वहां एनटीपीसी के द्वारा चार हजार मेगावाट का सुपर थर्मल पावर

प्लांट मिल रहा है और उसके द्वारा छः हजार लोगों को रोजगार मिला है। यह निवेश केन्द्र के द्वारा किया जा रहा है, केन्द्र की नीतियों के द्वारा किया जा रहा है। झारखंड में रोजगार का सृजन हो रहा है, लेकिन जिन उद्योग, नीतियों की जरूरत थी, राज्य सरकार द्वारा जो सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत थी, वह राज्य सरकार ने नहीं बनाई। अगर आज हमारे युवा बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, तो उस, जेएमएम, उस कांग्रेस सरकार के कारण हो रहे हैं, जो सरकार नहीं महाठगबंधन है। आज वह सबके सामने आ चुका है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर हमारे राज्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज ये सब होते हुए भी मैं शनिवार को गारंटी की गाड़ी के साथ था।

पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। यह गारंटी की गाड़ी है। मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी क्या है कि हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, हर गरीब को बिजली मिलेगी, हर गरीब को जल मिलेगा, हर गरीब को टॉयलेट मिलेगा, हर गरीब को गैस का चूल्हा मिलेगा, हर गरीब को बैंक का खाता मिलेगा। यह मोदी जी की गारंटी है। आज पूरे देश भर में जो गारंटी की गाड़ी चल रही है और मैं अपने विपक्ष के साथियों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आप भी इस गारंटी की गाड़ी के साथ चलिये। आप देखियेगा कि लोगों का कितना बढ़िया रिसेप्शन मिल रहा है। इसके द्वारा आपके ही क्षेत्र में अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं, सेचुरेशन मोड में इनको कुछ नहीं मिला है, तो आपके प्रयास के द्वारा छान-बीन में जो इक्के-दुक्के लोग मिलेंगे, उनको भी मोदी जी की गारंटी के द्वारा ये सब बुनियादी सुविधाएं आप ही दिलवा दीजिए। वे भी आपको धन्यवाद देंगे। आप पुण्य का काम कर लीजिएगा, जो हम सब लोग इस गारंटी की गाड़ी के द्वारा कर रहे हैं।

साथियों, मोदी जी की गारंटी के द्वारा, उनके कुशल नेतृत्व के कारण अगर हम मल्टी-डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के बेंचमार्क को देखें तो हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को उस गरीबी रेखा से आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। यह मोदी जी की गारंटी है। हम लोग 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि के द्वारा पैसे दे रहे हैं। हम लोगों ने कितने सारे लोगों को उज्ज्वला योजना दी है और वह संख्या लगभग 11-12 करोड़ है।

माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं, मैं अब उन नीतियों के बाद सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मोदी जी की जो गारंटी है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में भी पूरे तरीके से इसको स्पष्ट किया गया है। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में करीब 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का अधिक खर्च करने का प्रावधान है, लेकिन उसमें नेट कैश आउटप्लो सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये का है। आपने कहा कि जहां 1.29 लाख करोड़ रुपये सप्लीमेंटल खर्च करने हैं, उसमें से सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये एकचुअली नेट कैश आउटगो है। इतने किफायती तरीके से बजट को संभाला गया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने संभाला है कि नेट कैश आउटगो सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये है।

अगर इसकी तुलना की जाए, तो आप देखें कि जो फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल ट्रेजेक्टरी है, वह हम कितने अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों की माइक्रो-इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है और हम लोगों का ग्रोथ रेट इतना अच्छा है। अगर हम पिछले वर्ष की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को देखें तो जहां 1.29 लाख करोड़ रुपये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इस साल मांगा है, वही पिछले वर्ष 4 लाख 35 हजार करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मांगा था। इस बार हम 58 हजार करोड़ रुपये मांग रहे हैं, पिछली बार 3 लाख 25 हजार करोड़ रुपये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में मांगने पड़े थे। हम लोग कोविड से निकल रहे थे और रिकवरी के लिए स्पेंडिंग की जरूरत थी। रिकवरी में जो स्पेंडिंग हुई, वह इतने बढ़िया तरीके से हुई कि अब जीडीपी ग्रोथ रेट 7 परसेंट के पार हो रहा है और जो फिस्कल डेफिसिट है, वह कम होता जा रहा है।

जहां हमें 4 लाख 35 हजार करोड़ रुपये खर्च करने थे, अब हम सिर्फ एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। यह दिखा रहा है कि फिस्कल मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। अगर हमें यह अतिरिक्त खर्च करना है, तो किन क्षेत्रों में कर रहे हैं? जहां मोदी जी की गारंटी है, हम वहां खर्च कर रहे हैं। यह जरूरी है। नरेगा में 14 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट सब्सिडी मतलब बच्चों के लिए पोषण, सुप्रिया जी कह रही थी कि जनकल्याण, सामाजिक कल्याण के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम न्यूट्रिएंट सब्सिडी के लिए 14 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं तो सामाजिक कल्याण के लिए कर रहे हैं। हम लोग अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए, सेना को दुरुस्त बनाने के लिए अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

मैं एक बहुत ही विशेष बात बताऊंगा, जो मोदी जी की गारंटी से जुड़ा हुआ है, गारंटी की गाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग पूरे तरीके से सेचुरेशन मोड में करना चाह रहे हैं और वह उज्ज्वला योजना है। इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रैंट्स में साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये उज्ज्वला योजना के लिए और सप्लीमेंट्री डिमांड की गई है और जैसे मैंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। हमारे विपक्ष के साथी इससे जुड़ें। अगर आपके क्षेत्र में ऐसी कोई महिला हो, जिसे अभी उज्ज्वला योजना, गैस का सिलेंडर नहीं मिला है, उसके लिए इस बजट में पूरा प्रावधान है। सबको खोजिए और सबको उज्ज्वला सिलेंडर आप जरूर दिलवाइए।

फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए भी 13 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। सुप्रिया जी ने कहा कि किसानों के पक्ष में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। किसानों के लिए अगर हम लोग यूरिया सब्सिडी में 13 हजार करोड़ रुपये और खर्च कर रहे हैं और किसान सम्मान निधि के द्वारा उनको 6 हजार रुपये तो मिल ही रहे हैं। दो हजार रुपये की किश्त अभी आने भी वाली है। 15 नवम्बर को हमारे झारखंड के सभी माननीय सांसद साथी भी वहाँ थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खूँटी में दो हजार रुपये किश्त के रूप में किसानों को दिए। इस प्रकार से किसान क्षेत्र में जितना हम लोगों ने साधन दिया है और आगे भी देते चले जाएंगे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सुप्रिया जी, मैं मानता हूँ कि किसानों के लिए हम लोगों ने जो किया है, वह ऐतिहासिक और अतुल्य है। इसे आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सुप्रिया जी ने इसके अतिरिक्त दो कंट्राडिक्शंस की बात की। उनका मानना था कि अगर हम अपनी पावर पॉलिसी को देखें तो एक तरफ हम रिन्यूअल्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोयला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कोयला हम सबके लिए, विशेष रूप से झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर हजारीबाग के लिए, जहाँ मैंने अभी बताया कि 4 हजार मेगावाट का पीवीयूएनएल का थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। पकरी बरवाडीह में हम लोग करीब 15-16 मिलियन टन सालाना कोयले का खनन कर रहे हैं। पूरा वहाँ कोयले का खनन हो रहा है, पूरे क्षेत्र में कोयले का खनन हो रहा है। इससे हम लोगों के देश में बहुत हम लोगों को फायदा/लाभ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को बिजली की जरूरत है। सुप्रिया जी, बिजली की जरूरत क्यों है, माननीय विपक्ष के साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय जब हम लोगों की अपेक्षा थी कि पावर जनरेशन 7,8 या 6 परसेंट ही बढ़ेगा, वह आज के समय 9,10,11 या 12 परसेंट बढ़ रहा है। वह इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर न हो, हमारे पास एनर्जी न हो और हमारी ग्रोथ न हो पाए। यह हम लोगों के लिए शार्ट टर्म के लिए बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ कि इसमें कंट्राडिक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि ?नेट जीरो? हम लोग वर्ष 2070 तक हासिल करेंगे। आज के समय जो कोयला आ रहा है, आज के समय जो कोयले का उत्पादन हो रहा है, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट पतरातू में बना रहे हैं, पूरी तरीके से उसका उपयोग करते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त बनाते हुए, उसको हम लोग वर्ष 2070 तक रिटायर करके नेट जीरो हासिल कर लेंगे। यही इसकी एक पूरी तरीके से प्लानिंग है। आप इसको कंट्राडिक्शन न समझें, इसको आप लांग टर्म प्लानिंग समझिए। कोयले का भी उपयोग होगा और इस तरीके से तेजी से हम लोग रिन्यूअल्स भी लेते आ रहे

हैं। सुप्रिया जी, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी ?कॉप? चल रहा है, आपको मालूम है कि दुबई में बहुत बड़े पैमाने पर कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप चल रही है। आज जी-20 में सिर्फ एक देश है, जिन्होंने अपने सब नेशनली डिटर्मिन्ड कान्ट्रीब्यूशंस, पेरिस एग्रीमेंट के 2015 के एनडीसीज को पूरी तरीके से हासिल किया है। ? कॉप? में इसका ग्लोबल स्टॉक टेक चल रहा है। एक ही देश ने इसे पूरी तरीके से हासिल किया है, सफल रहा है और साथियों, वह देश भारतवर्ष है। आपका जो मानना है कि कंट्राडिक्शन है, बिल्कुल कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपको लांग टर्म समझना है, 2070 को समझना है। कोयले का भी सदुपयोग होगा, रिन्यूअल्स का भी सदुपयोग होगा।

जैसे मेरे माननीय साथी उदासी साहब बता रहे हैं कि पंप स्टोरेज हाइड्रो का भी बहुत तेजी से पूरे देश भर में उपयोग हो रहा है। जिस प्रकार से रिन्यूअल्स का ग्रोथ भारत में हो रहा है, उसका कोई मुकाबला कहीं भी नहीं है। यह भारत ही आपको दिखा रहा है।

एक ही विषय सदन में हर बार आता है, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि वे इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है और मैं थोड़ी-बहुत जानकारी इस विषय में रखता हूँ, इसलिए मैंने सोचा जरा एक बार फिर इसको बोल दूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार इसको समझाया है, लेकिन मैं फिर एक बार समझा दूँ कि जब बैंक के लोन का राइट-ऑफ होता है तो इसका मतलब क्या है। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, वे हरदम इस बात को उठाते हैं, वे कहते हैं कि बैंक के लोन का आपने राइट- ऑफ किया, आपके जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। सुप्रिया जी, यह गलत बात है। इसको आप ठीक तरीके से समझिए। अगर आप किसी भी बैंक के लोन पर एनपीए हो जाते हैं, डिफाल्ट हो जाते हैं, आईबीसी, जिसे हम लोगों ने ही पारित किया, इस सदन ने पारित किया, जिसके लिए सबका मानना है यह गेमचेंजिंग ऐतिहासिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, उसके तहत अगर आप एनपीए हो गए, डिफाल्ट हो गए, उसका एकदम स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि कंपनी आपके हाथ से गई। कम्पनी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में चली जाती है और हम रिकवरी में लग जाते हैं। यह कहना कि लोन का राइट ऑफ हुआ तो उद्योग वालों को हमने कुछ फेवर ग्रांट की है, यह बिलकुल गलतफहमी है। मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहता हूँ कि कहीं भी डिफाल्ट हो गया तो आपकी कम्पनी गई। वह कम्पनी बैंकों को मिल जाती है और बैंकों का रिकवरी का काम शुरू हो जाता है और जब हमें सही समय मिल जाता है तो रिकवरी अच्छी होती है और कई जगह बैंकों ने पूरी रिकवरी भी की है। इस प्रकार से आपको इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): जयंत जीआपके पास क्या राइट ऑफ रिकवरी के कोई आंकड़े हैं?

श्री जयंत सिन्हा : वे सब आंकड़े हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : यह आपको बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी दिखाता है कि हम फटाफट उसका राइट ऑफ ले रहे हैं, कम्पनियों को हम लोग हमारे हवाले कर रहे हैं और रिकवरी में फौरन ला रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, तब ऐसा होता था कि कम्पनी डिफाल्ट हो गई तो कम्पनी नहीं जाती थी। आप लोन को फोन बैंकिंग के द्वारा एवरग्रीनिंग करते थे और वह कम्पनी उसी उद्योग वालों के पास रहती थी। आप उन पर मेहरबानी करते थे, लेकिन हम मेहरबानी नहीं करते हैं, हम देश की जनता को उनका अधिकार देते हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : सुप्रिया जी, आपने कहा कि हमारी इकोनॉमी सेविंग्स की इकोनॉमी थी, लेकिन अब कंजम्पशन की इकोनॉमी बन गई है, लेकिन यह गलतफहमी है। वास्तव में हमारी इकोनॉमी निवेश की इकोनॉमी बन गई है, इनवेस्टमेंट की इकोनॉमी बन गई है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्टमेंट हो रहा है, कार्पोरेट सेक्टर में इनवेस्टमेंट हो रहा है। इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि निवेशक इस आंकड़े को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसका आम जनता पर भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। 20 साल पहले वर्ष 2004 में हमारी जीडीपी 0.7 ट्रिलियन डॉलर्स की थी। आज वर्ष 2024 में लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। हमारी मार्केट कैप टू जीडीपी रेश्यो है, वह लगभग 1:1 रहता है। पिछले 20 सालों में हमने शेयर बाजार में हमने जिस सम्पत्ति को हासिल किया है, वह करीब 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी की गारंटी के कारण, माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, माननीय प्रधान मंत्री जी के साहासिक निर्णयों के कारण आज हमारी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से अग्रसर है, वह 7 परसेंट, 8 परसेंट का ग्रोथ हो रहा है, जो 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। अगर इसे 20 साल आगे प्रोजेक्ट करें तो यह लगभग 15, 16 या 17 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हो जाएगी। पिछले 20 वर्षों में शेयर बाजार के अंदर जो 3 ट्रिलियन की सम्पत्ति का क्रिएशन हुआ है, आज के समय निवेशकों का मानना है कि अगले 20 साल में 12 ट्रिलियन का लक्ष्य, चार गुना ज्यादा का लक्ष्य हासिल करेंगे। यह सम्पत्ति निवेशकों को मिल रही है। सुप्रिया जी, आज के समय हमारे मिडल क्लास के लोग बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान खोल रहे हैं। वे हर महीने शेयर बाजार में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे उनकी सम्पत्ति भी बढ़ेगी और देश की सम्पत्ति भी बढ़ेगी। यदि एसआईपी के आंकड़े देखें तो मिडल क्लास का विश्वास नजर आएगा।

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : महोदय, ईपीएफओ का जो पैसा शेयर बाजार में जा रहा है, उससे पेंशन प्रोविडेंट फंड के जो हिस्सेदार हैं, उनकी सम्पत्ति भी बढ़ने वाली है। विदेश से पैसे तो आ ही रहे हैं, यदि हम आगे की तरफ देखें तो माननीय प्रधान मंत्री जी सही कहते हैं कि यह अमृत काल है और वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। यह प्रधान मंत्री जी की गारंटी है और इससे आप भी जुड़ जाइए। इससे आपका भी विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे एक्सेस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका अत्यंत ही आभारी हूँ।

महोदय, 1,29,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट इन अनुपूरक मांगों में प्रदान किया गया है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपये उर्वरकों के लिए और लगभग 7,000 करोड़ रुपये खाद्य पदार्थों के लिए दिया गया है। यह स्वागतयोग्य है। यह गरीबों और किसानों को भी कहीं न कहीं बहुत फायदा पहुंचाएगा क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण उर्वरकों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। किसानों को इसमें सही रूप से सब्सिडी दी जा रही है।

महोदय, हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पाँच सालों के लिए बढ़ाने का काम किया है। अतिरिक्त डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जो बजट दिया गया है, यह इसमें भी काम आएगा। लेकिन, हमें यह देखने की जरूरत है कि यदि इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में आज भी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है तो फिर हम कौन-से विकसित भारत में

रह रहे हैं? जो देश वैश्विक स्तर पर पाँचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, जो दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहता है, आज उसके 80 करोड़ लोग अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हैं, बल्कि 80 करोड़ लोग सरकार-निर्भर हो चुके हैं। कहीं न कहीं सरकार को इसे संज्ञान में लेना होगा कि लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर रहेंगे, उन्हें सरकारी अन्न के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रैंकिंग होती है, उसमें आज भी हमारे आंकड़े बहुत बुरे होते हैं। इसके साथ-साथ हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे बच्चों के अन्दर स्टंटिंग आती है। इसे भारत सरकार कह रही है कि बच्चों में स्टंटिंग और कमजोरी आती है। इसका मतलब कि पौष्टिक आहार के अभाव में उनकी जो ग्रोथ होनी होती है, वह पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। यह जो पैसा जा रहा है, जो खाने की गारंटी दी जा रही है, उसमें क्यों नहीं उसे पौष्टिक आहार की गारंटी दी जाती, जिसमें अंडा, प्रोटीन इत्यादि चीजें दी जाएं, जिससे बच्चों के अंदर स्टंटिंग की प्रॉब्लम न आए। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि यह खाना देने पर बच्चों में स्टंटिंग नहीं होगी और उनका बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास, दोनों विकास अच्छी तरह से होगा।? (व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): शाकाहारी लोगों के लिए सोया दिया जा सकता है।? (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : मैडम, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्हें सोया दिया जा सकता है। आपके क्षेत्र में बहुत सोया होता है। उनके लिए इसका प्रावधान किया जाए। मेरा मुद्दा यही है कि इसका प्रावधान किया जाए। शाकाहारी दिया जाए, सोयाबीन दिए जाएं। सोया के जो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट नगेट्स आते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए।

महोदय, फरवरी के बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ी उद्घोषणा की थी। उन्होंने एक विज़न दिखाया था। उन्होंने समृद्ध भारत की कल्पना की थी, जो समावेशी हो, समावेशी का मतलब कि सभी समाज के लोग उसके अन्दर हो। बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की बात करती है। बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखने का कार्य किया है और आज उनकी आवाज़ बनकर हम यहां पर आपके पास आए हैं। आपको यह बताना है कि कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। आज दलित पूरी तरह से पीछे छूटा हुआ है और उसका भी सच मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। इसको मैं अदम गोंडवी जी के एक शेर के माध्यम से उजागर करूंगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेर पेश करूँ। इसमें मैंने एक शब्द बदला है। मैं इस सदन के माध्यम से अदम गोंडवी जी से भी माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा है - ? अभी जब मैं अपने भाषण में आगे बढ़ूंगा तो यह उसके परिप्रेक्ष्य में है। उन्होंने कहा है -? आगे सुनिए कि ? में क्या हो रहा है। सवाल यह है कि क्या गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को समृद्धि नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहिए और उसका उत्तर यह है कि हम उसमें पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से यह बताया गया है कि दलितों के खिलाफ अपराध डबल हुए हैं। जहां वर्ष 2011 में 33,700 दलित उत्पीड़न के मामले थे, वहीं वर्ष 2020 में ये मामले बढ़ कर 50,251 हो गए हैं। आइए ले चलता हूँ ? आपको, महसूस कीजिए ज़िंदगी की ताप को। यह है ज़िंदगी ताप, हुज़ूर! इतने ज्यादा मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। यह देखिए, एनसीआरबी की यह भी रिपोर्ट है कि वर्ष 2019 के डेटा के ? विकास की यात्रा के बारे में बात की गई, लेकिन विकास की यात्रा का लक्ष्य अत्यंत ही दूर है। मैं यह किसी नकारात्मक सोच के तहत नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ कि हम यात्राएं ज़रूर निकाल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य को भी सामने साफ कर के देखें और लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हो रही है, उसका भी ब्यौरा यहां पर देने का काम करें। ऐसी स्थिति, जहां अपराधों का रोकथाम

करने के लिए अतिरिक्त बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिलना चाहिए, वहां अनुपूरक माँगों में इसका प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले, जब मेन बजट था, तो 38 पैसे दलितों और अल्पसंख्यकों के बजट को लेकर कटौती की गई थी। उसी के साथ-साथ, अभी जो अनुपूरक आया है, उसमें खानापूर्ति करने के लिए मात्र 73 लाख रुपये का, सर, 1 लाख 29 हजार करोड़ रुपये का बजट है, और दलित उत्पीड़न के लिए 73 लाख रुपये मात्र दिए गए हैं। सर, यह हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, यह बहुजन समाज का अधिकार है और यह अधिकार मिलना चाहिए। वहीं, हमें क्या देखने को मिलता है कि सीवर और नालियां, आज भी इस देश में लोगों को सीवर और नालियों के अंदर घुसना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है, बिना प्रोटेक्टिव गियर के काम करते समय। इस प्रकार की सफाई करने में ज्यादातर हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं और बजट में यह प्रावधान किया गया था कि मनुअल स्केवेंजिंग को खत्म कर दिया जाएगा। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह उद्देश्य एक दिवास्वपन रह चुका है। यह सिर्फ एक सपना दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी हमारे सामने है। सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 308 लोग मारे गए। सच्चाई यह है कि 308 के फिगर से कहीं ज्यादा लोग मारे गए होंगे। देश में 60 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड मनुअल स्केवेंजर्स हैं। इनमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। इसी के साथ-साथ मैं फिर से अदम जी का शेर यहां पर दोहराना चाहूंगा ? ? इस सदन के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। उसी के साथ-साथ, मैं यह भी आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ कि हमारे यहां दुनिया में कोई भी देश ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकांत जी।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर 369 के अंतर्गत है।

माननीय सदस्य ने अभी दो चीज़ों की बात कही है। एक तो उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जिक्र किया और दूसरा सामाजिक बात, मतलब जो लोग गटर में मर रहे हैं, उनकी बात कही है। ये दोनों सब्जेक्ट राज्य के विषय हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि वे उस पेपर को ऑर्थेंटिकेट करें, वे जो बातें कह रहे हैं, पेपर को ऑर्थेंटिकेट करें और सारे राज्यों का डेटा वे दें कि दलित की हत्या कौन कर रहा है, दलितों का रेप कहाँ हो रहा है? किस ? में, किस राज्य में लोग मर रहे हैं, यह ऑर्थेंटिकेट करें, नहीं तो इसको एक्सपंज किया जाए। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: जो गलत बात है, वह नहीं जाएगी।

? (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : सर, दलित उत्पीड़न राज्य का इश्यू नहीं है, देश का इश्यू है। यह एक बात है। दूसरा, मैं यहां पर अनुपूरक माँगों की चर्चा पर भाग ले रहा हूँ। मेरा मानना है कि ये जो अनुपूरक माँगें आई हैं। ? (व्यवधान) सर, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को कनक्लूड कर रहा हूँ। मेरा यह मानना है कि उनके लिए नए-नए यंत्रों की व्यवस्था की जाए। आज हम चन्द्रमा पर पहुंच गए हैं। हमारे पास बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, जो इंसान को भी पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन, गटर की सफाई के लिए मशीनें नहीं हैं। उसके लिए मेरा अनुरोध है कि अगर वित्त मंत्री जी अपने अनुपूरक में इसके बारे में सोच कर व्यवस्था की होती तो बहुत अच्छा होता।

अंत में, मैं अपने प्रदेश की दो बातें कह कह अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे यहां 69 हजार टीचर्स की भर्ती को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और लोग आंदोलित हैं। मेरे ख्याल से उसको भी लेकर सदन में एक सकारात्मक सोच के तहत उनको रिक्रूट करने की जरूरत है।

सर, इस अनुपूरक में छुट्टा पशुओं की लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए थी। छूटे सांड, गाय, बैल, बछड़े रोड्स पर आकर लोगों की जान ले रहे हैं। हमारे एकड़ के एकड़, हेक्टेयर के हेक्टेयर खेत बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी अनुपूरक में व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा बहुजन समाज मात खाता है।

अंत में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उस पीठ से बैठ कर पहली बार मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपके नेतृत्व में अपनी बात रख रहा हूँ।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत- बहुत धन्यवाद ।

SHRI JAYDEV GALLA (GUNTUR): Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the current Fiscal Year and also on the Demands for Excess Grants, the expenditure for which was incurred in 2020-21.

Sir, I was going through why the Government is seeking an additional Rs. 1.29 lakh crore, and trying to understand the justification for the same. Under the description, I found that Rs. 16,300 crore was allocated for the Nutrient Based Subsidy Scheme, and there was also some recoupment of Rs. 5,000 crore advance. But the Supplementary Demands show only Rs. 13,351 crore. So, there is a mismatch. I would like to know from the hon. Minister why there is a disparity and difference in the figures.

Secondly, Sir, the FM has allocated Rs. 1.7 lakh crore in Budget for the FY 2024 in respect of fertilizer subsidies. If you add Rs. 13,351 crore to it, it comes to Rs. 1.88 lakh crore. But if you look at the total expenditure in FY 2023, it was a whopping Rs. 2.55 lakh crore. So, now that we have a reasonably better monsoon, the outgo would be more. Since the cost of natural gas has also gone up, a higher amount would be needed for fertilizer subsidy.

Thirdly, in the first half of this Fiscal Year, we have already spent 65 per cent of the fertilizer subsidy. So, instead of coming before the Parliament again and again, why can the Finance Minister not have a holistic view of the fertilizer expenditure and move accordingly?

Sir, let me now come to the NREGA. The hon. Minister is seeking Rs. 14,524 crore. When the FM presented this year's Budget itself, the House was unanimous that

the allocation of Rs. 16,000 was not sufficient. It was 18 per cent below the allocation made in the previous year. But I would like to know from the hon. Finance Minister whether this is sufficient for the entire Financial Year since the demand is likely to increase in the coming months. Taking advantage of this, Sir, there have been demands from every corner of the country to increase the minimum number of days of work under NREGA to 150. Now, that AP has been battered by Cyclone Michaung and the people, particularly the farming community, have suffered badly, I would request the hon. Finance Minister to announce 150 days of work under NREGA and continue this on a regular basis going forward as well.

Sir, I also thank the hon. Prime Minister and also the hon. Finance Minister for releasing Rs. 493 crore to AP under the National Calamity Relief Fund to meet the expenses due to the Cyclone Michaung. After the Cyclone Michaung has left a trail of devastation in AP and Tamil Nadu, despite my previous appeal for Rs. 5,000 crore interim relief for Andhra Pradesh, only less than Rs. 500 crore have been disbursed so far. The President of the Telugu Desam Party, Shri Nara Chandrababu Naidu has urged the hon. PM to declare it as a national disaster. Over 22 lakh acres of crops in AP have been decimated with losses exceeding Rs. 10,000 crore. I request you to expedite the enumeration process, send a central team and release the funds swiftly to aid the distressed farmers many of whom have been seen committing suicides because of the financial impact on them.

Sir, the next point I wish to touch upon is about the borrowings. The hon. Finance Minister has set a target of market borrowings of nearly Rs. 15.5 lakh crore for this Fiscal Year. I think, in the first half of this Financial Year, the Government has already borrowed more than 60 per cent of that figure.

17.00 hrs

It means that the calculations and the borrowing plans appear to be going wrong, and the target of Rs.15.5 lakh crore may even go up to Rs.17 lakh crore or Rs.18 lakh crore at the end of this financial year. This will disturb the fiscal target of 5.9 per cent set by the Finance Minister for the FY 2024. Of course, we are getting consistent GST revenue of Rs.1.6 lakh crore. I request the hon. Finance Minister to explain to the House what the real picture is.

I would also like to know how much non-tax revenue the Government is expecting in the first half and also the dividends from the RBI and other public sector banks.

The next point is that the Finance Minister is seeking about Rs.483 crore under various Heads for the Jal Shakti Ministry. But I did not find anything for the Polavaram Project in AP. There are reports in the media that the Government is in the process of approving Rs.31,625 crore for the first phase of the Polavaram Project. I think the Jal Shakti Ministry has also approved this. I would like to just remind the hon. Finance Minister that she has approved release of Rs.12,911 crore on 5th June of this year. Works of Rs.16,000 crore have already been completed and works of Rs.15,000 crore are yet to be taken up. Now there is an additional Rs.2,600 crore needed for the first phase. Since the FM has already approved Rs.12,911 crore, I appeal, on behalf of the people of Andhra Pradesh, to kindly approve the first phase estimates of Polavaram Project and release the amount without any further delay.

The entire bifurcation of AP was done on the premise of Section 93 of the AP Reorganisation Act, 2014. Section 93 says that the Central Government will take all necessary measures as enumerated under the 13th Schedule for the progress and sustainable development of the State successively for a period of 10 years. Only a few months are left to complete 10 years. To be precise, only four months are left. We have been hearing about high level meetings between the Government of India and the Government of AP officials. One such meeting was held last month but nothing tangible is happening on the ground.

The Dugarajapatnam Port is the Government of India's guarantee. The AP Reorganisation Act says that the first phase should be completed by 2018. However, this project has not even been started.

The Metro Rail Project proposed in Visakhapatnam and Vijayawada-Guntur-Tenali is the Government of India's guarantee but these have also not started. I think some private developer has come forward to share 60 per cent of the cost of the project. I appeal to the hon. PM to please take this up.

The new railway zone is one of the Government of India's other guarantees. Rs.106.89 crore was sanctioned last year but it is only for the revenue expenditure. Rs.10 crore was given in 2023-24. The zone is yet to become a reality.

The greenfield crude oil refinery and petrochemical complex was Government of India's guarantee but nothing has happened.

The construction of educational institutions is running at a snail's pace and is not going to be completed within the prescribed time of 10 years. All I request is the

timely delivery of the hon. Prime Minister's and the Government of India's guarantees before the June, 2024 deadline comes up.

Coming to the excess grants, I wish to submit that these excess grants have been scrutinised by the Public Accounts Committee. It means that the Committee has scrutinised threadbare these grants. I have little to say on this since these excess grants are related to free foodgrains being given to the poor under the PMGKAY which has now been extended till 2028. I welcome this. A part is also related to the Atmanirbhar Bharat Scheme given during the pandemic. So, I have nothing to add here as well.

With these submissions, I support the Supplementary Demands and the Excess Grants placed before the House by the FM for their approval. Thank you, Sir.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I am here to express the views of the CPI (M) on the Supplementary Demands for Grants for the additional spending of Rs. 1.29 lakh crore.

Sir, before coming to the Ministry-wise demands for grants sought, I wish to bring to the notice of this august House how the financially imbalanced and unjustified attitude of this Government seriously affects the financial health of the States, including the State of Kerala.

The BJP Government's stance reminds me of Yayathi's story in Mahabharata which would be more familiar to my colleagues from the Treasury Benches. For those who do not know Yayathi's story, I would quickly glance through it. Yayathi was once cursed by his father-in-law Sukracharya for cheating her daughter. So, he lost his youth and became an old aged person.

Sir, however, on Yayathi's request, his 5th son Puru took over his old age in exchange of his youth and enjoyed his life for 1000 years. This is exactly what has happened in the case of GST. When the GST was introduced as 'One Nation, One Tax', the Government promised to compensate for the loss of revenues of the States and that is why they have agreed for such a game changer in tax proposal.

Now, after five years, even though revenues of the State Governments have not improved, the Union Government which is playing the role of neo-Yayati is enjoying the benefits and is not ready to share the benefits turning the States into neo-Purus.

Sir, I am speaking only the facts. There is no limit for the Union Government and its PSUs to borrow from open market. But when the State Governments are going for the same, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act stares upon them. In the case of Kerala, the Union Government is not even allowing it to borrow the mandated 3 per cent of its GSDP by unnecessarily reducing the borrowing limit quoting one reason or the other. The hon. Finance Minister was telling about the common yardstick for all States under Article 293(3) of the Constitution guided by the Finance Commission.

Sir, what is the total national debt of the Government of India? The national debt of India as on 31st March, 2023 was Rs.155.6 lakh crore, which comes is around 57.1 per cent of GDP, and this Government is restricting the State Governments from taking loans. What an irony, Sir!

Sir, Kerala is one of the few States which has shared the burden of land acquisition for widening of national highways in the State, and has already handed over an amount of Rs.5580 crore to National Highway Authority of India, as replied by Shri Nitin Gadkari Ji on the Floor of this House. I want to know from the Government why they have included this amount of Rs.5580 crore in the purview of the borrowing limit. Here, you are punishing Kerala for helping your Government, and the Ministry of Road Transport and Highways. Even this amount was reduced from the State's borrowing limit saying that this amount was borrowed by KIFFBI, the special purpose vehicle formed for off-budget borrowing.

Sir, same is the case with the funds of Kerala Social Security Pension Limited which is used for providing welfare pensions for more than 60 lakh people at the rate of Rs.1,600 per month. Not only that, this amount is deducted from Kerala's borrowing limit, the Central share for pension and welfare, paddy procurement, UGC teachers' salary and even noon-meal programmes of the State of Kerala.

An assessment by the State Government has shown that the total reduction in State finances due to the reduction in annual borrowing limit, cessation of GST compensation, decrease in revenue deficit grant and reduction in the *inter se* distribution from the divisive pool during the 15th Finance Commission is a whopping Rs.50,000 crore.

Sir, above all, the BJP Government has come up with a new tactic of withholding the funds in the name of branding. In Kerala, for houses built under LiFE Mission, which is the largest of its kind in the country, a total of Rs. 4,00,000 is spent on each

unit, and out of this, the Union Government is providing a meagre amount of Rs.72,000 as part of PMAY. When the Government of Kerala has constructed about four lakh houses and handed over the keys to the beneficiaries within seven years, the Government of India is insisting that these houses should display the logo of PMAY as if it was granted by the Central Government. The Government of Kerala is spending more than Rs.378 lakh per unit, but we are not asking for display of any sign or emblem.

Sir, it is a universally accepted fact that housing is the basic right, and I have only pity towards this Government for such an inhuman attitude towards lakhs of houseless people of this country. So, my humble request to the hon. Finance Minister is to treat the States at par with the Centre as per federal principles enshrined in our Constitution, and allocate their due shares in time. Specific to Kerala, I request that the borrowing limit be increased by one per cent over and above the annual borrowing limit for 2023-24 as a special case due to the present financial constraints of the State.

Sir, I bring to the attention of the hon. Finance Minister an issue having wider implication across the whole country, that is, the criteria for calculating CIBIL score. This issue is being faced by people all over the country. This is a very serious issue. Many a time borrowers of loans find it difficult to repay the loans due to unpredictable genuine circumstances in life, including health problems and job loss, and are, therefore, forced to settle the loan with the bank amicably on mutually agreeable terms. Even in such cases, the CIBIL score of people would be seriously affected as such loans are considered not closed but settled. There are lakhs of farmers and students who have taken agricultural loans and educational loans for their higher studies respectively and are affected by this.

Recently, the High Court of Kerala has ordered that the loans issued to farmers based on Paddy Receipt Sheet should not come under the purview of the CIBIL score of individual borrowers and I wish that the Minister would take note of it. In view of this, I request the hon. Minister to urgently give directions to the Reserve Bank of India to have a re-look at the criteria for calculating CIBIL score for the benefit of the common people of the country.

Sir, coming to Alappuzha parliamentary constituency which I represent, it is a long pending demand that the Government allocates the required amount for the doubling of the Ambalappuzha-Thuravoor stretch of the Railways. This is the only stretch in Kerala for which the Government has not allotted the required funds. I

would like to extend my sincere thanks to the hon. Finance Minister for the amount allocated for the doubling of Ernakulam-Thuravoor stretch.

Now, on behalf of the Government of Kerala and people of Kerala, I wish to make the following demands. The amount spent by the State towards the land acquisition cost of national highways may be compensated. The decision to reduce the borrowing limit of Kerala in the name of off-Budget borrowings since 2021-22 has to be reconsidered. The State entitlement under the CAPEX Scheme has to be relaxed immediately as it is a loan and not strictly a Centrally-sponsored scheme. The Union Government should release pending payment of various schemes as I mentioned earlier. I request the hon. Minister to consider the repeated requests of Government of Kerala to extend the period of GST compensation and a special package has to be announced for Kerala taking into account its resource loss due to the new tax policy of the Union Government.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): ज़नाब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने ज़िमनी मुतालबात पर बोलने का मौका दिया। शुरुआत में जब बजट पास हुआ जो हमें भरोसा दिलाया गया था कि मुल्क में तरक्की रफ्तार पकड़ेगी लेकिन मुतालबा ज़र पेश किया जा रहा है तो हमें अहसास हो रहा है कि जो हमारे हदफ़ थे, टार्गेट्स कहीं हमसे छूट रहे हैं। 1 लाख 29 हजार 348 रुपये के ज़र मुतालबात पेश किए गए। मुल्क की मजमुई तौर पर माशी हालत ठीक नहीं है, अनएम्पलाएमेंट, अंडर एम्प्लायमेंट बढ़ती जा रही है। बुनियादी सहूलियतें अवाम को मयस्सर नहीं हैं, ज़रात का शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर है। जहां तक जम्मू-कश्मीर की बात है, जम्मू-कश्मीर को अफसरशाही के हवाले किया गया, गैर-मुताखिब और गैर-जवाबदाह अफसरशाही के हवाले किया गया। इससे क्या हुआ, जम्मू-कश्मीर में और भी मुतासिर तरक्की की दौड़ हो गई। जनाब, जम्मू-कश्मीर में 61,000 के करीब डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, कॉलेज डेवलपमेंट फंड वर्कर्स, कन्टीन्जेंट पेड वर्कर्स, सीजनल टीचर्स और बाकी वर्कर्स अपनी रिकोग्निशन का कई साल से इंतजार कर रहे हैं।

रेगुलराइजेशन तो दरकिनार, उनको मिनिमम वेजेज भी नहीं दी जा रही हैं। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में मात्र 3 हजार रुपये के वेजेज कई-कई महीनों के बाद दिए जा रहे हैं। सारे मुलाजिम बड़ी परेशानी का शिकार हैं। होना यह चाहिए था कि रेगुलराइजेशन के लिए फौरी इंतजाम किए जाएं, ताकि इनके परिवार, जो इन पर निर्भर हैं, इनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनको रिलीफ मिले, लेकिन जो गैर-जवाबदेह इंतजाम है, जो अफसरशाही है, वह इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रही है।

जनाब, ट्राइबल्स की बात हो रही है। हमारे ट्राइबल्स जम्मू से श्रीनगर का रुख करते हैं और श्रीनगर से जम्मू का रुख करते हैं। उनके लिए सीजनल स्कूल्स बने हुए हैं, टीचिंग सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन वहां के उस्ताद केवल 6 महीने के लिए रखे जाते हैं और 6 महीने के लिए उनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाता है। यह उनकी बड़ी परेशानी है। जम्मू-कश्मीर में हेल्थ केयर सिस्टम 40 फीसदी के करीब मैन पावर पर चल रहा है, मैन पावर क्राइसेस का सामना कर रहा है। जो एक नैरेटिव खुशहाल कश्मीर का बनाया जा रहा है, उसमें कोई सदाकत नहीं है।

जनाब, 40 परसेंट कोई तरजीद नहीं कर सकता है। अगर मिनिस्टर साहब चाहें, तो तरजीद कर सकते हैं। केवल 40 फीसद मैन पावर पर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है। न ही कन्सल्टेंट, न ही डॉक्टर्स और न ही पैरा मेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जा रही है। जो मैन पावर पूल मौजूद है, उनको टेम्परेरिली रिक्रूट किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बगैर किसी राहत के छोड़ा जा रहा है। हमारे पास इक्यूपमेंट्स पड़े हैं। मैंने अपने एमपी लैड फंड से 5 करोड़ के करीब इक्यूपमेंट्स चार जिलों के लिए खरीदे, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। एक-एक ब्लॉक में एक रेडियोलोजिस्ट तक नहीं है। इस कारण सारे इक्यूपमेंट्स अस्पताल में बेकार पड़े हुए हैं। अनंतनाग में मैटरनिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है। एमआरआई के लिए कहा गया था। हमने पेट्स स्कैन के लिए कहा था। 25 लाख लोगों के लिए कोई पेट्स स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं और कोई कैथ लैब नहीं है।

जनाब, जल शक्ति में जो नल से जल की बात है, तो वहां के सेक्रेट्री ने ही निशानदेही की कि करीब 23 हजार करोड़ रुपये का घपला हुआ है। लोगों को खराब पानी पिलाया जा रहा है। साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। अगर हम बात करें डोगरीपुरा में, कालीबुग, खयूम आदि जगहों पर स्कीम्स हैं, पैसा लगाया हुआ है, लेकिन फिल्ट्रेशन का कोई इंतजाम नहीं है। इसके अलावा पावर का सबसे बड़ा मसला है। अभी सुप्रिया जी ने भी जिक्र किया था। 14 से 16 घंटे तक का शटडाउन रहता है। आज वहां 5 डिग्री तापमान है। इस सर्दी में 14 घंटे, 16 घंटे का शटडाउन है, पावर नहीं है, तो आप देखिए कि इस ठिठुरती सर्दी में क्या हाल होगा? आप किस खुशहाल कश्मीर की बात करते हैं? हमने कई पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो एनएचपीसी के हवाले किए गए। यह एग्रीमेंट बीओटी कहलाता है। इसका मतलब बिल्ट ऑपरेशन ट्रांसफर होता है। ये 25 साल पहले दिए गए और एनएचपीसी ने उससे सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया, लेकिन ट्रांसफर करने से कतराती है। हमारा जम्मू-कश्मीर 3215 मेगावाट बिजली पैदा करता है, लेकिन वहां 16 घंटे की डेफिसिट है। करीब 16 घंटे का शटडाउन है और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे उस परेशानी से जूझ रहे हैं।

जनाब, जहां तक वहां पर कैपेक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला है, ऋषिपुरा ब्रिज, डोगरीपुरा ब्रिज, पटलवा ब्रिज आदि के लिए फंड की बात है कि उनको कम्प्लीट किया जा सके। करोड़ों रुपये वहां लगाए गए, लेकिन अभी तक उन पर कोई काम शुरू नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, वे ट्रांसफर नहीं हो रही हैं। जहां पर जो हेल्थकेयर फैसिलिटी है, वह हो ही नहीं रही है। यह है वहां की गवर्नमेंट डेफिसिट। वहां पर कोई फैसले लेने के काबिल नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है।

जनाब, इसके अलावा रोज-रोज वहां पर व्हीकल्स के एक्सिडेंट्स की परेशानियां हैं। जोजिला में पिछले दिनों दो एक्सिडेंट्स हो गए, जिसमें जानें चली गयीं। टूरिस्ट्स केरल से आए हुए थे, जिनकी जानें चली गईं। डोडा में 35 जानें चली गईं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, ताकि व्हीकल्स के एक्सिडेंट्स का लॉग टर्म में कोई सॉल्यूशन हो जाए। उसमें एक बात यह है कि जब जवाबदेही नहीं रही तो उसके बारे में कोई तवज्जो कहीं पर नहीं है। यही हाल राशन का है। यही नरेटिव बनाया जा रहा है।

जनाब, एक बात जरात की है और दूसरा एनवॉयरमेंट मिलाकर यही दो इश्यूज हैं। एनवॉयरमेंट में हमारा सामना एनवॉयरमेंट डिग्रेडेशन और एनवॉयरमेंट चैलेंज का है। हमारे एरिया में पम्पोर है। वहां पर जो पॉल्यूशन है, इमीशन्स हैं, सैफरन हमारी कैश क्रॉप की सबसे बड़ी पैदावार थी, वह 22000 किलो ग्राम से घटकर अब 4000 किलोग्राम पर आ गया है, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है।

جناب، وہاں پر جے.کے.سیमेंٹ لیمیٹڈ کا ایک سرکاری اڈارا تھا، وہ بند کر دیا گیا، شٹ-ڈاؤن کیا گیا۔ اب شاید اُسکو اڈاणी جی کے ہوالے کرنے کا من بنایا جا رہا ہے؟ (ببببببب) وہاں کوئی کئرینگ کپیسٹی نہیں ہے۔ وہاں اب ماہول نہیں ہے کی اور پالوشن برڈاشٹ کیا جاے۔

جناب، وہاں کے جو مولاجیم ہیں، جس پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے، وہ پینشن کے لیے پانچ سال سے اڈتجار میں ہیں۔ وہاں ہم نے فیسلا کیا تھا کی کوئی اور سیमेंٹ پلانٹ کو بننے نہیں دینگے۔ اُسکے ببببببب ہمارے مولالبے کی اندےخی کی جا رہی ہے۔ اُسکو اڈاणी جی کو یا کسی اور دینے کا پراس کیا جا رہا ہے، جسکی ہم مولالبف کرینگے۔ ہم پورجور تریکے سے کھینگے کی کوئی اڈیشن ن ہو۔

جناب، وہاں پر ہم نے 35 کروڈ روپے سے ایک فیسلیٹی بناڈی تھی، جو سئفرن کی جیآئی ٹرینگ کے لیے تھی۔ آپ ہران ہینگے کی وہاں پر ماٹر 85 کیلوگرام کا ہو گیا ہے، ببببببب پداوار ہی بخت ہو گڈی۔ جو پراڈم مینسٹر نیشنل سئفرن مشن 500 کروڈ روپے کا تھا، اُسمیں سئفرن کے لیے سٹریکل اڈریشن کی ببببببب کی گڈی۔ جناب وہ ساری کی ساری بند پڈی ہیں سرکار کو مولالبف ہوا، اُسکی جانچ کرایڈ جاے، ایک ان-ڈیٹھ انکوائری کرایڈ جاے کی کسے یہ فیل ہوا؟ جو ہمارا چار ارب روپے کے سئفرن کراپ کا کاروبار ہوتا تھا، اُسکو کسے ریسٹور کیا جاے؟

جناب، ان چیجوں کی طرف تببببببب دینے کی جربور ہے۔ بببببببب شکریا۔

[جناب حسنین مسعودی صاحب (انٹ ناگ): چیرمین صاحب، بببببببب شکر یہ آپ نے مجھے]
ضمنی مطالبات پر بولنے کا موقع دیا۔ شروعات میں جب ببببببب پاس ہوا تو ہمیں ببببببب دیا گیا تھا ملک میں ترقی کی رفتار آگے بڑھے گی، لیکن مطالبہ زر پیش کیا جا رہا ہے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ہدف تھے وہ کہیں ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ 1 لاکھ 29 ہزار 348 روپے کے جو زر مطالبات پیش کئے گئے، ملک کی مجموعی طور پر معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان ایمپلائمنٹ، انڈر ایمپلائمنٹ بڑی جا رہی ہے۔ بنیادی سہولیات عوام کو میسر نہیں ہے۔ زراعت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے، جموں کشمیر کو افسر شاہی کے حوالے کر دیا گیا، غیر منتخب اور غیر جوابدہ افسر شاہی کے خلاف اس کے حوالے کیا گیا۔ اس سے کیا ہوا، جموں کشمیر میں ترقی کی دوڑ اور بھی متاثر ہو گئی۔ جناب جموں کشمیر میں 61000 کے قریب ڈیلی وچرس، کیڑول ورکرس، نیٹ ویسل ورکرس، ہوسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ ورکرس، کالج ڈیولپمنٹ فنڈ ورکرس، کنٹینینٹ پیڈ ورکرس، سیزنل ٹیچرس اور باقی ورکرس اپنی ریکوگنیشن کا کئی سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ ریکولرائزیشن تو درکنار، ان کو مینیم وچرز بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ ہوسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ میں صرف 3 ہزار روپے کے وچرز کئی۔ کئی مہینوں کے بعد دئے جا رہے ہیں۔ سارے ملازم بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریکولرائزیشن کے لئے فوری طور پر انتظام کئے جائیں، تاکہ انکی فیملی جو ان پر منحصر ہیں، ان کے بچے جو اسکول جاتے ہیں، ان کو ریلیف ملے، لیکن جو غیر جواب دہ انتظام ہیں، جو افسر شاہی ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔

جناب، ٹرائبلس کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ٹرائبلس جموں سے سری نگر کی طرف رخ کرتے ہیں ار سری نگر سے جموں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے لئے سیزنل اسکول بنے ہوئے ہیں، ٹیچنگ سٹرس بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کے اُستاد صرف 6 مہینے کے لئے رکھے جاتے ہیں اور 6 مہینے کے لئے ان کو بالکل برخاست کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی بڑی پریشانی ہے۔ جموں کشمیر کا ہیلتھ کیئر سسٹم 40 فیصد کے قریب مین پاور پر چل رہا ہے، مین پاور کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، جو ایک نیریٹیو خوشحال کشمیر کا بنایا جا رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

جناب 40 فیصد کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ اگر منسٹر صاحب چاہیں تو تردید کر سکتے ہیں۔ صرف 40 فیصد میں پاور پر ہمارا ہیلتھ کیئے سسٹم چل رہا ہے۔ نہ ہی کنسلٹنٹ ہیں، نہ ہی ڈاکٹرس اور نہ ہی پیرا میڈیکل اسٹاف کی ریکروٹمنٹ کی جارہی ہے۔ جو میں پاور پول موجود ہے، ان کو ٹیمپریلی ریکروٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کو بغیر کسی راحت کے چھوڑا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایکویمنٹس پڑے ہیں۔ میں نے اپنے ایم۔پی۔لیڈ۔ فنڈ سے 5 کروڑ کے قریب ایکویمنٹس 4 ضلعوں کے لئے خریدے، لیکن ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک۔ایک۔ بلاک میں ایک ریڈیولوجسٹ تک نہیں ہے۔ اس وجہ سے سارے ایکویمنٹس اسپتال میں بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اننت ناگ میں میٹر نٹی اسپتال کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہاں کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایم۔آر۔آئی۔ کے لئے کہا گیا تھا۔ ہم نے پیٹس اسکین کے لئے کہا تھا۔ 25 لاکھ لوگوں کے لئے کوئی پیٹس اسکین نہیں، ایم۔آر۔آئی۔ نہیں اور کوئی کیتھ لیب نہیں ہے۔

جناب، جل شکتی میں جو نل سے جل کی بات ہے، تو وہاں کے سیکریٹی نے ہی نشاندہی کی کہ قریب 23 ہزار کروڑ روپے کا گھپلا ہوا ہے، لوگوں کو خراب پانی پلایا جا رہا ہے۔ صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈوگری پورہ میں، کالی بگ، خیوم وغیرہ جگہوں پر اسکیمس ہیں، پیسہ لگایا ہوا ہے، لیکن فلٹریشن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی سپریا جی نے بھی ذکر کیا تھا۔ 14 سے 16 گھنٹے تک کا شٹ ڈاؤن رہتا ہے۔ آج وہاں منفی 5 ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ اس سردی میں 14 گھنٹے، 16 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن ہے، پاور نہیں ہے، تو آپ دیکھئے کہ اس زبردست سردی میں کیا حال ہوگا؟ آپ کس خوش حال کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے کئی پاور پروجیکٹس بنائے ہیں، جو این۔ایچ۔پی۔سی۔ کے حوالے کئے گئے۔ یہ ایگریمنٹ بی۔او۔ٹی۔ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب بلٹ آپریشن ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ 25 سال پہلے دئے گئے اور این۔ایچ۔پی۔سی۔ نے اس سے سارا ریوینیو کلیکٹ کر دیا، لیکن ٹرانسفر کرنے سے کتراتی ہے۔ ہمارا جموں کشمیر 3215 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، لیکن وہاں 16 گھنٹے کی ڈیفیسٹ ہے۔ قریب 16 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن ہے اور لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس پریشانی سے جوجھ رہے ہیں۔

جناب، جہاں تک وہاں پر کپییکس اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، رشی پورا برج، ڈوگری پورا برج، پٹلوا برج وغیرہ کے لئے فنڈ کی بات ہے کہ ان کو مکمل کیا جا سکے۔ کروڑوں روپے وہاں لگائے گئے، لیکن ابھی تک ان پر کوئی کام شروع نہیں ہو رہا ہے۔ ہوسپٹل بلڈنگس جو بنی ہوئی ہیں، وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہیں۔ جہاں پر جو ہیلتھ کیئر فیسلیٹی ہے، وہ ہو بھی نہیں رہی ہے۔ یہ ہے کہ وہاں کی سرکار کوئی فیصلہ لینے کے قابل نہیں ہے، کسی کی کوئی جوابدہی نہیں ہے۔

جناب، اس کے علاوہ روز روز وہاں پر ویکلس کے ایکسیڈینٹس کی پریشانیاں ہیں۔ جوجیلا میں پچھلے دنوں دو ایکسیڈینٹس ہو گئے جس میں جانیں چلی گئیں۔ ٹورسٹس کیرل سے آئے ہوئے تھے، جن کی جانیں چلی گئیں۔ ڈوڈا میں 35 جانیں چلی گئیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تاکہ ویکلس کے ایکسیڈینٹس کا لونگ ٹرم میں کوئی سولوشن ہو جائے۔

اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب جوابدہی نہیں رہی تو اس کے بارے میں کوئی توجہ کہیں پر نہیں ہے۔ یہی حال راشن کا ہے۔ یہی نیریٹیو بنایا جا رہا ہے۔

جناب، ایک بات زراعت کی ہے اور دوسرا ماحولیات ملا کر یہی دو ایشوز ہیں۔ انوائرمٹ میں ہمارا سامنا انوائرمٹ ڈیگریڈیشن اور انوائرمٹ چیلنج کا ہے۔ ہمارے ایریا میں، پمپور ہے۔ وہاں پر جو پولیوشن ہے، ایمیشن ہے، زافران ہماری کیش کروپ کی سب سے بڑی پیداوار تھی، وہ 22 ہزار کلو گرام سے گھٹ کر اب 4 ہزار کلو گرام پر آ گیا ہے، کیونکہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے۔

جناب، وہاں پر ہے۔ سیمینٹ لمیٹڈ کا ایک سرکاری ادارہ تھا، وہ بند کر دیا گیا، شٹ ڈاؤن کیا گیا۔ اب شاید اس کو اڈانی جی کے حوالے کرنے کا من بنایا جا رہا ہے۔ (مداخلت) وہاں کوئی کینٹرنگ کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہاں اب ماحول نہیں ہے کہ اور پولیوشن برداشت کیا جائے۔

جناب، وہاں کے جو ملازم ہیں، جس پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے، وہ پینشن کے لئے 5 سال سے انتظار میں ہیں۔ وہاں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی اور سیمینٹ پلانٹ کو بننے نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود ہمارے مطالبے کی اندیکھی کی جا رہی ہے۔ اس کو اڈانی جی کو یا کسی اور کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی ہم مخالفت کریں گے، ہم پرزور طریقے سے کہیں گے کہ کوئی ایڈیشن نہ ہو۔

جناب، وہاں پر ہم نے 35 کروڑ روپے سے ایک فیسلٹی بنائی تھی، جو زافرن کی جی۔آئی۔ ٹیگنگ ک لئے تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر صرف 45 کلو گرام کا ہو گیا ہے، کیونکہ پیداوار ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو پرائم منسٹر نیشنل سیفرون مشن 500 کروڑ روپے کا تھا، اس میں سیفرون کے لئے اسپرنکل ایریگیشن کا انتظام کیا گیا۔ جناب، وہ ساری کی ساری بند پڑی ہے، میرا سرکار سے مطالبہ ہوگا اس کی جانچ کرائی جائے، ایک ان ڈیپتھ انکوائری کرائی جائے کہ کیسے یہ فیل ہوا؟ جو ہمارا 4 ارب روپے کے سیفرون کروپ کا کاروبار ہوتا تھا، اس کو کیسے ری اسٹور کیا جائے؟

جناب، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ

[ختم شد]

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you, Sir. In all our approach to economy and whenever we analyse the policies related with economy in relation to our development agenda, disability has to be taken as identity. We will not be able to achieve the goal of social justice without inclusion of persons with disability in all spheres of development.

Globally, 1.3 billion people, which is equal to the entire population of India live with some kind of disability. Nearly, 80 per cent of them live in developing countries, and 70 per cent live in rural areas. These people are experiencing higher instances of poverty, lack of access to education and opportunity, and various kinds of social and economic discrimination.

As per a recent study conducted by the International Labour Organisation, inclusion of persons with disabilities can help boost global GDP between three and seven per cent. In our country also this has to be the criteria, namely helping the poor, and bringing forthwith positive and creative policies and implementing them for the upliftment of the poor, farmers, working-class, minorities, backward classes, etc. The welfare of the nation will be made possible only by ensuring rights of the persons with disability.

Here, I am drawing the attention of this august House to a Japanese example. Actually, when we take the case of Japan today, which is the third largest economy

by GDP in the world, in Japan there is reportedly a death by suicide every 20 minutes. Even though, the country has achieved such an important financial, economic growth and development, it is facing very serious social problems. There is a death by suicide every 20 minutes. Nearly 15 lakh Japanese have not left their homes for years, which is a kind of severe social withdrawal that is named as hikikomori.

Sir, all the parents rent actresses to come in on Sundays to call them mom and pop because their own daughters do not visit them anymore. In our country also, nowadays, the children are not taking any interest in looking after their parents. This is the technological havoc and tsunami. The earnings of the children are not helpful for their own parents. As the poet said, 'ज़िंदा लार्शों की भीड़ है चारों तरफ़, मौत से भी बड़ा हादसा है जिंदगी?' It is a very serious situation.

The *Vraddha Sadans* are increasing in our country. In Japan, lonely deaths are taking place. Every day, dead persons are found in Japan in their tiny apartments days and weeks after they die. These lonely deaths are called 'Kodokushi'. It is a coincidence that in our language of Hindi and in Urdu, 'suicide' is called 'Khudkushi' and in Japan, lonely deaths are called 'Kodokushi'. Japan has climbed to 3rd position in the global economy. It has not lifted all boats. It has tossed the weak to the margins to languish. The economic growth on steroids has destroyed the safety net of family and community ties. High value industrial economy has taken the centre stage. It has destroyed the family ties and the social relationships. In our country also, the economic condition is being challenged by technological tsunami and havoc.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, I need two minutes. Artificial intelligence will give jobs, but it will not give jobs to the poor and backward classes. It will give jobs only to the affluent and those who have skills in that field. Similarly, in Japan, young men from the countryside migrated to cities for salaried jobs, but they were not trained in that kind of jobs. So, they were not able to get such jobs. And the result was that they fell through the cracks into financial collapse, which resulted in social withdrawal.

The technological risks that confront the world today have created a very serious situation. People are more and more dependent on the digital network. As a result, digital economy is coming into existence. Our Government is also speaking of

digital economy. It is a very, very serious situation in a period when the truth itself becomes casualty. For example, the real risk is the 'deep fake' feature. Even our Government will have to take very serious steps to tackle this situation. The situation needs extra vigilance. Most of the people in our country still remain marooned in the slow lanes.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, I am concluding. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana will be extended by five years. That means 80 per cent people of India will be getting free grains to stave off their hunger by the year of 2028. This 2028 is the year in which the Government expects India to become the third largest economy of the world.

While concluding, I want to ask a question to the Government. Will such a large population of India still be suffering from hunger? Who will benefit from the five-year dash of our country to meet these targets? They are putting forth their concepts of digital economy, GST, Insolvency, Bankruptcy, decrease in corporate tax, and many other things like Make in India, Start-up India quite often. Are these tools and sectors helpful for the people?

While concluding, I request that an environmental, sustainable, and socially-harmonious future will have to include the poor people, the backward people, the disabled people into the mainstream of economy. I request the Government to take strong and positive steps in this direction.

With these words, I conclude my speech.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स पर बोलने का मौका दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एनडीए सरकार ने गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस सब्सिडी में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर 100 रुपये की बढ़ोतरी की। इस निर्णय से 9.6 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में लक्षित सब्सिडी योजना के अंतर्गत आते हैं। एनडीए सरकार द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित सभी घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलजीपी) उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कीमत में कटौती की है और तीन वर्षों में अन्य 75 लाख गरीब परिवारों को कवर करने के लिए पीएमयूवाई कवरेज का विस्तार किया।

सभापति जी, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने एलपीजी गैस सिलिंडर पर जो सब्सिडी प्रदान की है, उससे करोड़ों लोगों और विशेषकर हमारी बहनों को जो फायदा हुआ है, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किसानों को सस्ती कीमतों

पर उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी की सीजन 2023-24 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार पहल को वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल छः महीने में गंभीर धन की कमी का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़े 6,146.93 करोड़ रुपये के घाटे का संकेत देते हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटित बजट शुरुआती अनुमानों की तुलना में 18 प्रतिशत कम और पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़ों की तुलना में 33 प्रतिशत कम है।

सभापति जी, मनरेगा कार्यक्रम की मांग-संचालित प्रकृति है और रोजगार के अवसरों की मांग के अनुरूप है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर फंड जारी करना है, जिससे रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसका संज्ञान लेते हुए प्रधान मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी को तुरंत मनरेगा संचालन को बनाए रखने के लिए पूरक बजट की मांग के निर्देश दिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो योजनाएं मज़दूरों, किसानों तथा गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन योजनाओं के लिए धन की कमी न हो।

सभापति जी, आज पूरे देश में आदरणीय प्रधान मंत्री जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत की यात्रा चल रही है और उस विकसित भारत का सपना पूरा करने का प्रयास महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब भी कर रहे हैं। उनको माननीय उप मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस और माननीय उप मुख्य मंत्री अजीत पवार पूरा सहयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसानों को राहत देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी किसानों के लिए एक रुपये में इश्योरेंस स्कीम डिक्लेयर की है और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता के लिए पांच लाख रुपये के मेडिकल इश्योरेंस 'महात्मा ज्योतिबा फूले योजना' जारी की है। वहां महिलाओं के लिए 50 परसेंट ट्रैवलिंग में कंसेशन दिया हुआ है और बच्चों को लखपति बनाने की योजना भी चालू की है। महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का इम्प्लिमेंटेशन चालू है और उसके लिए केन्द्र सरकार का भी सहयोग चाहिए। महाराष्ट्र की विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार का सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत राशि महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध न होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार की एक डिमांड है कि कृषि उन्नति योजना, जिसका बजट 7,066 करोड़ रुपये का बजट है, लेकिन उसमें 373 करोड़ रुपये ही रिलीज हुए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 7,150 करोड़ का बजट अमाउंट है, लेकिन उसमें 165 करोड़ ही रिलीज हुआ है।

एक्सलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम की बजेटेड कॉस्ट 3122 करोड़ रुपये है और उसमें केवल 24 करोड़ रुपये ही रिलीज हुए हैं। आंगनवाड़ी पोषण अभियान की बजेटेड कॉस्ट 20554 करोड़ रुपये की है लेकिन उसके 1172 करोड़ रुपये ही रिलीज हुए हैं। मिशन वात्सल्य (child protection and child welfare) की बजेटेड कॉस्ट 1472 करोड़ रुपये है, लेकिन जीरो अमाउंट रिलीज हुआ है। आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की जो डिमांड है, उसको निश्चित रूप से आप पूरी करेंगी।

आखिर में, मैं महाराष्ट्र के किसानों की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से महाराष्ट्र राज्य के प्याज उत्पादक किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई किसान सड़क पर आ गए हैं और महाराष्ट्र राज्य के नासिक सहित अन्य जिलों में किसानों ने आंदोलन भी शुरू किया है और कई जिलों में किसान आंदोलन करने के कगार पर हैं। प्याज का निर्यात सही समय पर नहीं किया गया तो प्याज सड़ जाएगी और किसानों का भारी नुकसान होगा।

महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर एनडीए गठबंधन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कटिबद्ध है और इसी श्रृंखला को मानते हुए सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की ज्यादा आय सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों योजनाओं को अपनाया और लागू भी किया है। पहले ही बेमौसम भारी बारिश से प्याज उत्पादक किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और अचानक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगने से किसानों की आमदनी के रास्ते बंद हो जाएंगे और किसान हतबल हो जाएगा। प्याज का निर्यात बंद होने से किसानों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। आपके माध्यम से मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जी का भी रिकवैस्ट है कि महाराष्ट्र राज्य में प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए और महाराष्ट्र के किसानों को राहत दी जाए।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूं।

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon Chairman Sir, Vanakkam. The Government of the day claims through statistics that India has become an economic super power in the world. Similarly through statistics the Government says that India has achieved an economic growth of more than seven per cent. We can only assess whether India has achieved economic growth or not during the last 10 years only by way of assessment made on the lives of the people. The Government of the day should understand what is left behind after this assessment. Agriculture is so predominant in providing employment. I should say that the rural economy has completely been shattered during the BJP rule. Unprecedented urbanisation is a result of this shattered rural economy. Urbanisation means that the rural economy is on the verge of destruction. Agriculture which is the backbone and lifeline of rural areas is seeing a decline and destruction. That's why rural people are migrating to towns and cities and urban areas.

Secondly, 92 per cent of employment is provided by MSMEs in India. Again I should mention here that MSMEs are on the verge of destruction. During the last 10 years, MSMEs have reached a dying state. Tiruppur is a commercial centre and hub. As much as 50 per cent of industries here in Tiruppur are in a dying state. Many of them are not functional as on date are closed. Defective economic policies of the Government in power are the reason for this decline. MGNREGA, 100 days employment guarantee Scheme has shrunk and it seems that in future they will gradually wind up this scheme. This MNREGA Scheme was the one good Scheme which provided employment to some extent to the people in rural areas. But now the Government of the day has put hurdles in the implementation of this Scheme. I urge that the MGNREGA beneficiaries should be given Rs. 400 as daily wage

besides providing them 200 man days of regular employment in one year. GST should not be levied on MSMEs. Levying GST is affecting the MSMEs. I therefore request that MSMEs should be completely exempted from GST. Similarly, Textile Industrial hubs are very much affected. Next to Agriculture, the Textile Industry provides employment on a large scale. Textile Industry is shrinking day by day. These are the reasons as to why unemployment is on the rise.

The Government and those in Government earlier had assured to provide two lakh jobs every year. They should accept their defeat and regret for their inability to provide two Crore jobs per year as assured by them. They have not provided two Crore jobs every year. The ground reality is that more than six Crore people have lost their jobs. Our Economic Advisor to the Government says that the country will achieve development only when Adanis and Ambanis get development. Adanis and Ambanis do not create social assets. Rural farmers and urban labourers are the ones who create social assets. Government should ponder over providing subsidies and facilities to such farmers and labourers who create social assets. GST should be waived off for MSMEs completely.

Those in the Government talk about Jawaharlal Nehru very often. Even the Home Minister said the current situation in Kashmir is because of Pandit Nehru. I should say the PSUs created by Pandit Jawaharlal Nehru are privatised and are being sold to private parties by the Government. The income generated by these PSUs is being diverted to private players as the Government is selling one PSU after the other to them. This Government has committed a mistake by doing this. How can they assure that India has achieved growth? Education is being privatised. Education and health are two sectors which are taken away from people. Who are the ones affected by the ill effects of privatisation? It is the people of this county. People face difficulties in getting education as well as health facilities. They also talked about GDP data.

This Government has introduced contract labour in almost every sector. Why are they not going for providing permanent employment? Why are they offering contractual employment in regular jobs? I urge that this system of engaging contract labourers should be abolished in both government and private sectors. This Government is creating opportunities to exploit the labour force. I urge upon you that this system of contract labour should be given up. All senior citizens immediately when they attain 60 years of age should be provided assured pension of Rs 6000 per month. Union and State Governments should ensure that ASHA

workers who work hard even in hilly and remote areas be made permanent employees and their salaries be paid well in time. Malayali tribes have been granted the status of ST in other districts of Tamil Nadu. But In Erode district these Malayali tribes are not included in the list of STs. I urge that the Malayali tribes of Erode district be included in the list of STs and facilities be extended to them. With these words I conclude. Thank you.

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर): सभापति महोदय, कवि ने लिखा है :

Balo balo balo sobe

Shoto bina benu robe

Bharat abar Jagat sobhai

Shreshtho asono lobe

आज पूरे विश्व में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत सरकार देश चला रही है, किसी दूसरे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा भारतवर्ष कभी नहीं चला। एक बच्चे का जन्म होने के बाद उसे सबसे ज्यादा जरूरत खाने की होती है। उसे हेल्थ की जरूरत होती है। उसको घर की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है और फार्मिंग की जरूरत होती है। आज भारत के माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी खाने के लिए पूरे भारतवासियों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। उनको हेल्थ के लिए पांच लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है। उनको प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। शिक्षा की नई नीति बन रही है। किसानों के लिए किसान योजनाएं आ रही हैं। मैं यह जानता हूँ कि मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हमारे सीनियर मित्र सौगत दा बोल रहे थे कि इतने अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को ग्रांट नहीं मिल रहा है। आज मैं डिमांड कर रहा हूँ। आप जो यह पिकचर देख रहे हैं, यह एक मां की है। उनको शिक्षा और भिक्षा नहीं मिल रही है, चाकरी नहीं मिल रही है। वह हजार दिनों से धरना पर बैठी थी। कल भी वह माथा मुंडन करके रास्ते में थी। एक हजार दिन हो गए, फिर भी सौगत दा की सरकार कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल के किसानों को साइक्लोन से जो क्षति हुई, उनके लिए हम मदद चाहते हैं। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार मदद नहीं करेगी। हमारी नई डिमांड है। इतने अच्छे काम हो रहे हैं, तभी डिमांड हो रही है। पश्चिम बंगाल के रेलवे के लिए 12 हजार करोड़ रुपए की डिमांड पास हुई थी। हमारे भारतवर्ष के लोग जब विदेश में जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो सभी कहते हैं कि भारत आएंगे। यही नरेन्द्र मोदी जी का श्रेष्ठ भारत है। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतना अच्छा था, इतना हो रहा है।

जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल भारत की घोषणा की थी, उस समय किसी ने नहीं कहा। एक सीनियर लीडर कह रहे थे, जो वर्ष 2014 में आए थे, वे कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। वे कह रहे थे कि सब्जी वाले कैसे डिजिटल भारत करेंगे। आज सब्जी वाले कह रहे हैं कि हमें यूपीआई, पीटीएम और फोन-पे से पेमेंट कीजिए। यही डिजिटल भारत है। हमारा भारत माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जा रहा है, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल पीछे जा रहा है। हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको डीए नहीं मिल रहा है। उसको धक्का देकर राज भवन से आउट करना पड़ रहा है। आज हमारी नगरी में चोरी होती है। वहां पर खाद्य और

राशन का मंत्री, फूड मिनिस्टर जेल में है। बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है। वहां पर यूसी नहीं मिल रहा है। वहां का पैसा कहां जा रहा है?

वित्त मंत्री जी से मेरी डिमांड है कि पश्चिम बंगाल को पैसा भेजिए, लेकिन उसका यूसी भी लेना चाहिए, क्योंकि नगरी में जालियत, हर जगह में जालियत। हमारा पूरा भारतवर्ष आगे जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि भारतवर्ष में बुलेट ट्रेन हो सकती है। हमारे माननीय मੈम्बर कह रहे थे कि जापान में यह हो रहा है, वह हो रहा है। कांग्रेस की सरकार ने कभी सोचा कि भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी? यह कभी सोचा कि चंद्रयान सफल होगा? हमारे प्रधान मंत्री जी ने ये सब सोचा और करके दिखाया। यह सबसे बड़ी बात है। आज भारतवर्ष में कोई खाने के लिए नहीं रोता है। स्टेट गवर्नमेंट, विरोधी पक्ष के लोग रोते हैं कि हमारे लिए 100 रुपए आते हैं, लेकिन यहां पर हमें 16 पैसे मिल रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं। जब सारा पैसा इधर से भेज रहे हैं तो उधर जा रहा है। पश्चिम बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि पश्चिम बंगाल में जो साइक्लोन आया है, उससे बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके लिए कुछ ऐसी योजना बनाइये कि डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स के पास जाए। जो पोटैटो के फार्मर्स हैं, पोटैटो की खेती करते हैं, वे उसे मंडी तक नहीं ले जा पाएं, क्योंकि खेत में ही फसल खत्म हो गई।

मेरा भारत श्रेष्ठ भारत है। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे जाएंगे। यहां पर जो लोग बोल रहे थे कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, मैं यह बोलूंगा कि भारत आगे जाएगा और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि सभापति पैनल के अंतर्गत आप यहां विराजे और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

सदन में आज वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों व वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है। इन अनुदान मांगों के माध्यम से एक लाख 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने की मंजूरी सदन के माध्यम से मांग की गई है।

इस चर्चा को लेकर जब मैं समाचार पत्रों के डिजिटल एडिशन को देख रहा था तो उसमें यह बात सामने आई कि संसद में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रस्ताव में 58,378.21 करोड़ रुपये का कुल नकदी व्यय शामिल है। अतिरिक्त व्यय में खाद सब्सिडी पर 13,351 करोड़ रुपये का खर्च भी शामिल है। चूंकि खाद की सब्सिडी की बात आई है, मैं राजस्थान से आता हूं, डीएपी यूरिया को लेकर बहुत बार खाद की कमी भी आ जाती है और हम यहां बात भी करते हैं। सरकार का प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी आए दिन खाद की जितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल रही है। किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती हैं और किसानों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। मेरी मांग रहेगी कि हर साल उर्वरकों की किल्लत से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप मांग के क्रम में आपूर्ति को समय पर निर्धारित करें, ताकि खाद की किल्लत किसानों को न हो तथा और अतिरिक्त सब्सिडी किसानों को मिले।

मेरा दूसरा विषय सिंचाई और पेयजल का है। मैं राजस्थान स्टेट से आता हूं। पंजाब राज्य से राजस्थान की नहरों में सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिल रहा है और आए दिन आंदोलन राजस्थान में होते हैं। कई बार किसानों ने सीने पर गोलियां भी खाईं और अपने हक व अधिकार के लिए लड़ाई राजस्थान के किसान लड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, रसायन युक्त पानी पीने का पानी है। वह भी पंजाब से राजस्थान के करीब 12-13 जिलों के अंदर आ रहा है और वहां से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम कैसर ट्रेन है, जहां से ज्यादातर कैसर के मरीज

आते हैं। लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी इंदिरा गांधी नहर के अंदर जाता है और वह पीने का पानी राजस्थान के कई जिलों में जाता है। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा प्रयास करे कि साफ-सुथरा पानी राजस्थान के प्रत्येक इलाके में आए। यह मेरी बड़ी डिमांड है।

मैं आपका ध्यान राजस्थान के जल विवादों की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1981 में रावी-व्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर हुए समझौते के अनुरूप आज भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। 41 वर्षों से यह बात राज्य सरकारों और केंद्र में रही सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण लंबित है।

सभापति महोदय, यमुना बेसिन राज्य से हुए समझौते के अनुरूप भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई से सम्बन्धित अत्यंत महत्वपूर्ण ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग लम्बे समय से चल रही है। प्रधान मंत्री जी राजस्थान के चुनाव के अंदर गए, उससे पहले भी गए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का उस समय हवाला दिया गया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बन गई और दिल्ली में आपकी सरकार है तो ईआरसीपी का तोहफा बिना राजनीतिक भेदभाव के आपको राजस्थान के 13 जिलों को देना चाहिए, जो राजस्थान के उन 13 जिलों में एक संजीवनी साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट विधान सभा में मिले और लोक सभा के अंदर भी 25 सीटें राजस्थान ने एनडीए गठबंधन को दी थीं।

सभापति महोदय, मैं सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि शासन के नीतिगत निर्णय का लाभ वास्तव में समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि केवल भाषण में बड़ी-बड़ी बातें करने से देश का भला हो जायेगा। किसान, गरीब, मजदूर, रेहड़ी चलाने वाले लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, सेना में प्रवेश लेना हमारे देश में गौरव का विषय माना जाता रहा है। सेना में लोग रोजगार के लिए नहीं जाते थे। उनमें एक जज्बा है। उन्होंने वर्ष 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयां, कारगिल की लड़ाई, आज़ादी से पहले की लड़ाइयां लड़ी थीं। सेना के अंदर जो रेजिमेंट बनी हुई है, जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल है, सिख रेजिमेंट है। हमने एक और मांग की थी कि गुर्जर रेजिमेंट भी बने। जो जातियां लड़ना चाहती हैं, नौजवानों के अंदर एक इच्छा होती है कि हम सेना के अंदर जाकर देश के लिए समर्पित होंगे। जो अग्निपथ योजना आयी, उसका हमने बार-बार यहाँ विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग में विरोध किया। 4 साल के लिए जो संविदा पर, सेना को ठेके पर दिया, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं माँग करता हूँ कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले, नहीं तो लोक सभा चुनाव के अंदर यह मुद्दा इनके गले की फाँस बन सकता है। यह मेरी सरकार से माँग है। इसको लेकर हमने लगातार आन्दोलन किए हैं और आगे भी हम आन्दोलन करते रहेंगे।

महोदय, महँगाई से आम आदमी त्रस्त है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का प्रत्यक्ष असर महँगाई पर पड़ा और एनडीए की सरकार का जब वर्ष 2014 के अंदर बनी थी, तब के कूड ऑयल की कीमतों को देखें और अब तक के सफर पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। कूड ऑयल उस समय महँगा था और अब सस्ता है। उसके बावजूद बढ़ी हुई डीजल-पेट्रोल की कीमतें जनता को देनी पड़ रही हैं। मेरी माँग है कि घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए और महँगाई कम करने के ठोस उपाय किए जाएं।

महोदय, बेरोजगारी देश के अंदर बहुत प्रमुख मुद्दा है। भारत सरकार ने बताया कि 9 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। मेरी माँग है कि सरकार केन्द्र के मंत्रालयों, विभागों में रिक्त पदों के नवीनतम आंकड़े जारी करे और जल्द से जल्द उन्हें नियमित भर्ती के माध्यम से भरने के कदम उठाए। केन्द्र एक ऐसी नीति बनाए और राज्य सरकारें भी नियमित भर्ती से ही रिक्त पदों को भरें, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में बढ़ता निजीकरण देश के युवा वर्ग के लिए चिंता का विषय है। मेरा एक सुझाव है कि जब तक हम सीमेंट फैक्ट्रियों, उद्योगों, रिफायनरी जैसे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत रोजगार देने की नीति नहीं बनाएंगे, तब तक पलायन नहीं रूकेगा और बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा। स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए। महोदय, मेरी कुछ प्रमुख मांगें हैं। कृषि की बढ़ती लागत और फसलों की गैर लाभकारी कीमतों के कारण मेरे प्रदेश राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों के किसान कर्जों के तले दबे हुए हैं। आपका भी प्रयास रहा। हमने भी प्रयास किया। कर्जमाफी के आन्दोलन को देश में हवा मिली। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करें। जिस तरह पिछले 15-16 सालों के अन्दर धन्ना सेठों का 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह राजस्थान और देश के किसान का कर्जा माफ हो। एमएसपी पर किसान की पूर्ण उपज खरीदने का गारंटी कानून बनाया जाए। जो फसलें एमएसपी के दायरे में हैं, उनकी समय पर खरीद नहीं हो पाती, इसकी समय पर खरीद शुरू करने हेतु प्रभावी नीति बनाने की जरूरत है। महोदय, अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने राजस्थान में शुष्क कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की, परन्तु वह घोषणा आज तक पूरी नहीं हो पाई। इस पर सरकार ध्यान दे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागौर में सरकार से सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी खोलने की मैं मांग करता हूँ। मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने जातिगत जनगणना की मांग की।

महोदय, मैं और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जातिगत जनगणना कराने की पक्षधर है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के किसानों की जमीन अवाप्त की गई, लेकिन पंजाब, हरियाणा और अन्य दूसरी स्टेट्स के अंदर जो जमीन का मुआवजा दिया गया, उससे राजस्थान के अंदर मुआवजा बहुत कम था। जब हम गडकरी जी से इस मामले में मिले, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार नहीं कर रही है। अब तो राजस्थान में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। आप उन किसानों को, जिनकी जमीनें आपने अवाप्त की, जो बेघर हो गए, उनको जमीन की सस्ती कीमत मिली। उससे दोगुनी, तीन गुनी कीमत पर, पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के किसानों को भारतमाला योजना जमीन अधिग्रहण योजना के अंदर मुआवजा मिले।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी केंद्रीय कर्मियों को ओल्ड पेंशन योजना से लाभान्वित करने हेतु सरकार की ओर से कदम उठाया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में बोई जाने वाली विश्वविख्यात पान मेथी को मसाला कमोडिटी में शामिल करते हुए जीआई टैग दिया जाए। राजस्थान के जोधपुर प्रखंड किशनगढ़ तथा उदयपुर व जयपुर हवाई अड्डों में उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि जब तक नीति निर्माण में किसानों, गरीबों और मजदूरों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक इस देश में सही मायने में अमृतकाल नहीं आ पाएगा। किसान आंदोलन के समय किसानों के साथ जो समझौता हुआ था, उसके अंदर यह बात कही थी कि किसानों की सारी मांगें मानी जाएंगी। दुर्भाग्य से आज तक ऐसा नहीं हुआ है।? (व्यवधान) मेरी यह मांग रहेगी कि किसानों की सारी मांगें मानकर उस समझौते की क्रियान्विति सरकार करे।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): महोदय, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से आता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक रास्ते का इनोग्रेशन करने के लिए औरंगाबाद से महज 25 किलोमीटर दूर नारायण गांव नाम के एक छोटे से

गांव में गया। वहां पर एक जर्जर सी टूटी-फूटी इमारत के ऊपर के ऊपर नजर पड़ी तो यह पता चला कि यह सरकारी स्कूल है। टीन का शेड है, पक्की छत नहीं है, पानी टपकता है, जब बारिश होती है। वहां पर 200 बच्चे पढ़ते हैं। तीन छोटे-छोटे क्लास रूम्स वहां पर हैं। मैंने पूछा कि ये 200 बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं, तो पता चला कि 100 बच्चे क्लास रूम्स में बैठते हैं और 100 बच्चे बाहर ग्राउंड के ऊपर एक महीने के लिए बैठते हैं। एक महीने के बाद बाहर वाले बच्चे अंदर जाते हैं और अंदर वाले बच्चे बाहर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सोचने वाली बात है।

माननीय सभापति : जलील जी, कल आप अपना भाषण कंटीन्यू कीजिएगा, क्योंकि छह बज गए हैं।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : सभापति जी, इस समय को माइनस कर दीजिए, नहीं तो कल आप कहेंगे कि बैठ जाओ, आपका समय हो गया है।

माननीय सभापति : ठीक है। सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Tuesday, December 12, 2023/Agrahayana 21, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of
Business

in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

[*](#) Treated as laid on the Table.